शुक्रवार, 20 फरवरी 2026

मौसम

तापमान 19 – 31
आर्द्रता 55%
सूर्योदय: 06:06 सूर्यास्त: 17:35

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आ सुव।।

Epaper.samagya.in

समाज्ञा

एआई सम्मेलन में अंबानी, अदाणी के समूहों ने 210 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता जताई पृष्ठ 8

स्थानीय खबरें पृष्ठ तीन, चार और पांच पर

कोलकाता, फाल्गुन शुक्लपक्ष तृतीया, वि.स. 2082, पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

सुविचार : दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता।

आयोग ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अप्रैल में संभावित एसआईआर के लिए तैयार रहने को कहा

नयी दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है, क्योंकि इस प्रक्रिया के अप्रैल से शुरू किये जाने के आसार हैं। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) इसके दायरे में आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के अखिल भारतीय एसआईआर का आदेश पिछले साल जून में दिया गया था। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभी जारी है।

मुफ्त की स्कीमों पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को लगाई फटकार, कहा-

रेवड़ी नहीं रोजगार के अवसर पैदा करें

सबको फ्री सुविधाएं बांटना गलत

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, राज्य सरकार ने कुछ समुदायों के लिए बिजली टैरिफ में सब्सिडी स्कीम की घोषणा की थी। इससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर फाइनेंशियल दबाव पड़ा। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्यों में अपनाई गई मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा डालती है।

कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत समेत जजों ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा ज्यादातर राज्य पहले से ही घाटे में हैं, फिर भी विकास को छोड़कर मुफ्त सुविधाएं बांट रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा- जो लोग भुगतान नहीं कर सकते, उन्हें सहायता देना समझ में आता है। लेकिन अमीर-गरीब में फर्क किए बिना सबको मुफ्त देना गलत नीति है। इस दौरान कोर्ट ने चेतावनी दी और कहा अगर सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, साइकिल और बिजली मिलती रही तो लोगों में काम करने की भावना कम हो जाएगी।

'विकास के कामों के लिए पैसा कहां से आएगा?'

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'कई राज्य सरकारें भारी कर्ज और घाटे के बावजूद मुफ्त योजनाएं बांट रही हैं। अगर सरकारें मुफ्त पैसे, बिजली या दूसरी सुविधाएं देती रहेंगी, तो आखिर इनका खर्च कौन उठाएगा? अगर सरकारें मुफ्त खाना, साइकिल और बिजली जैसी सुविधाएं देती रहेंगी, तो विकास के कामों के लिए पैसा कहां से आएगा?' सीजेआई ने कहा कि कई राज्य पहले से ही घाटे में हैं, फिर भी वे नई-नई कल्याण योजनाएं शुरू कर रहे हैं। कोर्ट ने कैश ट्रांसफर व मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करने की वित्तीय समझदारी पर सवाल उठाया और कहा कि राज्यों को मदद बढ़ाने के बजाय रोजगार पैदा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

कोर्ट ने राज्यों को दी सलाह और पूछा सवाल

वहीं कोर्ट ने राज्यों को सलाह दी कि मुफ्त चीजें बांटने के बजाय, रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा, भारत में हम कैसी संस्कृति बना रहे हैं? क्या यह वोट पाने की नीति नहीं बन जाएगी? फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई में तय होगा कि ऐसे मुफ्त बिजली योजनाओं पर क्या नियम लागू होंगे।

एआई की वैश्विक यात्रा में 'आकांक्षी भारत' के लिए महत्वपूर्ण भूमिका : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के प्रमुख सीईओ के साथ एआई पर की चर्चा

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में कदाचार की संभावनाओं को असीमित बताते हुए इसके नैतिक उपयोग के लिए सुझाव दिए जिनमें डेटा संप्रभुता का सम्मान करना और पारदर्शी सुरक्षा नियम बनाना शामिल है। मोदी ने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में नेताओं के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वैश्विक यात्रा में 'आकांक्षी भारत' के लिए एक प्रमुख भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत भगवान बुद्ध की भूमि है जिन्होंने कहा था कि सही कर्म सही समझ से आता है और इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि हर कोई एक साथ आकर एक ऐसा रोडमैप तैयार करे जो एआई के सही प्रभाव को दर्शाता हो। मोदी ने यहां भारत मंडपम में विश्व नेताओं की उपस्थिति में कहा, ''और सही प्रभाव तभी पड़ता है जब हम सही समय पर, सही इरादे के साथ सही निर्णय लेते हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में अनैतिक व्यवहार की संभावनाएं असीमित हैं

और इसीलिए, सभी को एआई के लिए नैतिक व्यवहार एवं मानदंडों के ढांचे का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा, ''एआई कंपनियों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।'' मोदी ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए तीन सुझाव दिए जिनमें डेटा संप्रभुता का सम्मान करना; एआई प्रशिक्षण के लिए सभी के द्वारा एक स्पष्ट डेटा ढांचा तैयार करना शामिल है। उन्होंने कहा कि एआई प्लेटफॉर्म को अपने सुरक्षा नियमों को बहुत स्पष्ट और पारदर्शी रखना चाहिए। मोदी ने कहा कि एआई को स्पष्ट मानवीय मूल्यों की भी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, ''प्रौद्योगिकी शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन दिशा हमेशा मनुष्यों द्वारा ही निर्धारित की जाएगी।'' 'यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस' (यूपीआई) की कार्यकुशलता पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी भारत ने यूपीआई के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि लोग आसानी से भुगतान कर सकें और यूपीआई ने डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, ''हाल के वर्षों में, हमने एक जीवंत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया है। हम इसे दुनिया के साथ भी साझा कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए प्रौद्योगिकी शक्ति का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है।''

नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में, जल्द ही पूरी तरह समाप्त होगा : सीआरपीएफ महानिदेशक

गुवाहाटी : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक जी.पी. सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मार्च तक देश से इस समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। बल के महानिदेशक (डीजी) सिंह ने गुवाहाटी में बल की डीजी परेड को संबोधित करते हुए कहा कि सीआरपीएफ ने पिछले साल अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियानों में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए हैं। उन्होंने सीआरपीएफ की 'जनरल ड्यूटी' बटालियन और कोबरा कमांडो की भूमिकाओं को रेखांकित करते हुए

कहा, नक्सलियों के खिलाफ अभियानों में हमने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियानों में निर्णायक कदम उठाए गए हैं। सिंह ने कहा, ''नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की है, उसी के अनुसार मार्च 2026 तक यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।'' जम्मू कश्मीर में अपने बल की भूमिका का उल्लेख करते हुए महानिदेशक ने कहा कि यह आतंकवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियानों में शामिल है। उन्होंने भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में शिविर स्थापित करने तथा उन क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मियों की सराहना की।

आई-पैक पर छापेमारी के दौरान दखल देकर ममता ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया : ईडी ने न्यायालय से कहा

नयी दिल्ली/कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य तंत्र पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कोयला चोरी घोटाले के संबंध में आई-पैक कार्यालय और उसके निदेशक के परिसरों पर छापेमारी के दौरान 'अवैध रूप से दखल देकर सत्ता का घोर दुरुपयोग' किया। जांच एजेंसी ने राज्य सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि ममता और पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को का वेश धारण किए सशस्त्र व्यक्तियों' को अनधिकृत तलाशी लेने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। ईडी ने कहा कि उसके अधिकारियों ने आठ जनवरी को छापेमारी और तलाशी के दौरान पुलिस अधिकारियों को अपने पहचान पत्र विधिवत दिखाए थे। ईडी ने उच्चतम न्यायालय में अपने प्रत्युत्तर में कहा कि तथ्यों का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से ही पश्चिम बंगाल राज्य के तंत्र द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग स्पष्ट होता है। राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निजी हितों के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी के अधिकारियों के कार्यों के निर्वहन में बाधा डाली। राज्य सरकार के इस दावे को खारिज करते हुए कि मामला संघीय संबंधों से जुड़ा है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता, ईडी ने कहा कि वह राज्य के पदाधिकारियों द्वारा 'सत्ता के घोर दुरुपयोग' और उनके द्वारा किए गए अपराधों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किये जाने का अनुरोध कर रही है। जांच एजेंसी ने दावा किया कि पुलिस बनर्जी को उस परिसर में लेकर गई जहां तलाशी चल रही थी और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। जांच एजेंसी ने कहा कि कुछ व्यक्तियों ने ईडी अधिकारियों द्वारा एकत्र दस्तावेज ले लिए। कंप्यूटर और ईमेल डेटा के बैकअप की प्रक्रिया भी बीच में ही रोक दी गई। बनर्जी ने राज्य पुलिस अधिकारियों की सहायता से परिसर से एक कंप्यूटर को जबरन अपने अधिकार में ले लिया। ईडी ने कहा कि राज्य पुलिस ने बनर्जी के निर्देश पर परिसर में मौजूद मेसर्स पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों के मोबाइल फोन जबरन ले लिए। जांच एजेंसी ने कहा कि उन्होंने उसके अधिकारी का लैपटॉप और एक मोबाइल फोन ले लिया और दो घंटे बाद लौटाया। ईडी ने कहा कि लैपटॉप और मोबाइल फोन को ले जाना और दो घंटे तक अपने कब्जे में रखना चोरी के बराबर है।''

रामकृष्ण परमहंस के लिए 'स्वामी' शब्द पर मुख्यमंत्री ममता ने जताई आपत्ति

पीएम मोदी ने रामकृष्ण परमहंस को 'स्वामी' कहकर किया संबोधित

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर सोशल मीडिया पोस्ट में 'स्वामी' शब्द का इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने राज्य की 'महान हस्तियों के प्रति सांस्कृतिक असंवेदनशीलता' दिखाई है। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में 'स्वामी' संबोधन का इस्तेमाल किया है जबकि उन्हें व्यापक रूप से 'ठाकुर' उपनाम से संबोधित किया जाता है। इस दिन, उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया कि फिर से स्तब्ध! एक बार फिर हमारे प्रधानमंत्री ने बंगाल की महान हस्तियों के प्रति अपनी

सांस्कृतिक असंवेदनशीलता को आक्रामक ढंग से पेश किया है। आज युगावतार रामकृष्ण परमहंसदेव की जन्मतिथि है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर महान संत का सम्मान करने की कोशिश में हमारे प्रधानमंत्री ने उनके नाम के साथ एक अप्रत्याशित और अनुचित शब्द 'स्वामी' जोड़ दिया। ममता ने कहा कि रामकृष्ण को श्रद्धा से ठाकुर (ईश्वर के समान) कहा जाता था। उनके निधन के बाद उनके संन्यासी शिष्यों ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और भारतीय परंपरा के अनुसार उन संन्यासियों को 'स्वामी' कहा गया। लेकिन उन्हें ठाकुर के रूप में ही

जांच एजेंसियां बैंक खातों से लेन-देन रोकने के मामले में मनमानी नहीं कर सकतीं: उच्च न्यायालय

प्रयागराज (उप्र) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि साइबर धोखाधड़ी मामलों की पड़ताल कर रहीं जांच एजेंसियों के निर्देश पर बैंक खातों से लेन-देन रोकने के मामले में कोई भेदभाव या मनमानी नहीं की जा सकती है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ साइबर धोखाधड़ी मामलों से जुड़े बैंक खातों से लेन-देन रोकने के संबंध में अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की जांच कर रही है। तारकेश्वर तिवारी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने कहा, ''हमारे समक्ष विभिन्न रिट याचिकाओं से पता चलता है कि बैंकों ने खातों से लेन-देन रोक दिया है और जब ग्राहक उनसे संपर्क करते हैं, तो उन्हें केवल यह सूचित किया जाता है कि खाते पुलिस अधिकारियों या साइबर अपराध थाने द्वारा दिए गए पत्र पर फ्रीज कर दिए गए हैं।''

मैक्रों ने भारत-फ्रांस संबंधों को अद्वितीय बताया

मैंक्रों ने भारत-राफेल सौदे का किया पूर्ण समर्थन

डील से भारत की रक्षा क्षमता, रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे

नयी दिल्ली : भारत द्वारा फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लेने के कुछ दिनों बाद, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि मेक इन इंडिया इस कार्यक्रम का एक मुख्य घटक होगा। उन्होंने कहा कि फ्रांस भारत के साथ पनडुब्बियों पर सहयोग बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति 'एआई इम्पैक्ट समिट' के इतर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ रणनीतिक साझेदारी नहीं है, बल्कि एक विशेष वैश्विक रणनीतिक सा-

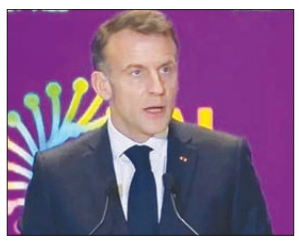

झेदारी है जो भारत और फ्रांस दोनों के लिए अनूठी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्ष रक्षा, नवाचार और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। राफेल खरीद कार्यक्रम से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि फ्रांस रखरखाव और क्षमता निर्माण के पहलुओं में सहयोग बढ़ाना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन पहले ही भारत ने राफेल की नई खेप की खरीद की इच्छा जताई है... और मेक इन इंडिया इसका एक प्रमुख पहलू होगा। उन्होंने कहा, मौजूदा सहयोग को स्पष्ट रूप से मजबूत करने की दिशा में यह एक नया कदम है। भारत ने अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा अधिग्रहण अभियान के तहत, पिछले सप्ताह फ्रांस के साथ सरकार-से-सरकार ढांचे के तहत 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, 'मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट' (एमआरएफए) परियोजना के तहत, राफेल निर्माता डसॉल्ट एविएशन द्वारा 18 विमान उड़ान भरने की स्थिति में आपूर्ति किए जाएंगे और शेष विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

सीएए विरोधी याचिकाएं: न्यायालय पांच मई से याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह संशोधित नागरिकता अधिनियम, 2019 (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली आईयूएमएल की प्रमुख याचिका सहित 200 से अधिक याचिकाओं पर पांच मई से अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। सीएए का उद्देश्य हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदायों से संबंधित उन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए थे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 2019-2020 से लंबित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के संबंध में प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए।

डीआरडीओ ने गगनयान 'ड्रोग पैराशूट' के लिए मुख्य परीक्षण किया

नयी दिल्ली : भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा किए गए परीक्षण ने उच्च क्षमता वाले 'रिबन पैराशूट' के डिजाइन और निर्माण में भारत की विशेषज्ञता को साबित किया है। रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह परीक्षण 18 फरवरी को चंडीगढ़ में 'टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी (टीबीआरएल) में डीआरडीओ के 'रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड' (आरटीआरएस) प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। इसमें कहा गया, ''भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ने गगनयान कार्यक्रम के लिए 'ड्रोग पैराशूट' के सफल विशिष्टता स्तर भार परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।'' मंत्रालय ने कहा कि इस परीक्षण से उच्च क्षमता वाले 'रिबन पैराशूट' के डिजाइन और निर्माण में भारत की विशेषज्ञता साबित हुई। यह परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, डीआरडीओ के 'एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट' और टीबीआरएल की विभिन्न टीमों के सहयोग से आयोजित किया गया। आरटीआरएस एक विशेष गतिशील परीक्षण प्रतिष्ठान है जिसका उपयोग उच्च गति वाले वायुगतिकीय और बैलिस्टिक मूल्यांकन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गगनयान 'ड्रोग पैराशूट' के सफल विशिष्टता परीक्षण पर डीआरडीओ, इसरो और उद्योग जगत की सराहना की है।

ईरान संकट गहराने से शेयर बाजार सहमा, चौतरफा बिकवाली से सेंसेक्स 1,236 अंक लुढ़का

भारी गिरावट से निवेशकों की संपत्ति करीब सात लाख करोड़ रुपये घटी

मुंबई : अमेरिका और ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से उपजी चिंताओं के बीच बृहस्पतिवार को चौतरफा बिकवाली से घरेलू शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,236 अंक टूट गया जबकि निफ्टी 365 अंक लुढ़ककर 25,500 अंक से नीचे आ गया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स तीन सत्रों से जारी तेजी पर विराम लगाते हुए 1,236.11 अंक यानी 1.48 प्रतिशत टूटकर 82,498.14 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 1,470.05

अंक फिसलकर 82,264.20 अंक पर आ गया था। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 365 अंक यानी 1.41 प्रतिशत लुढ़ककर 25,454.35 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी एक समय 430.6 अंक के नुकसान के साथ 25,388.75 अंक तक आ गया था। निफ्टी में गिरावट इस कदर व्यापक रही कि समूह में शामिल 50 में से 47 कंपनियों के शेयर गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स की कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अदाणी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, आईटीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट रही। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक निवेशक धारणा को प्रभावित किया, जिससे बाजार में व्यापक बिकवाली देखने को मिली।'' नायर ने कहा कि कच्चे तेल के साल के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच जाने से मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं बढ़ीं और होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आपूर्ति बाधित होने की आशंका के चलते बाजार में अस्थिरता बढ़ी। बीएसई पर सूचीबद्ध कुल 2,927 शेयर नुकसान में बंद हुए जबकि 1,276 शेयरों में तेजी रही। 164 अन्य के भाव अपरिवर्तित रहे।

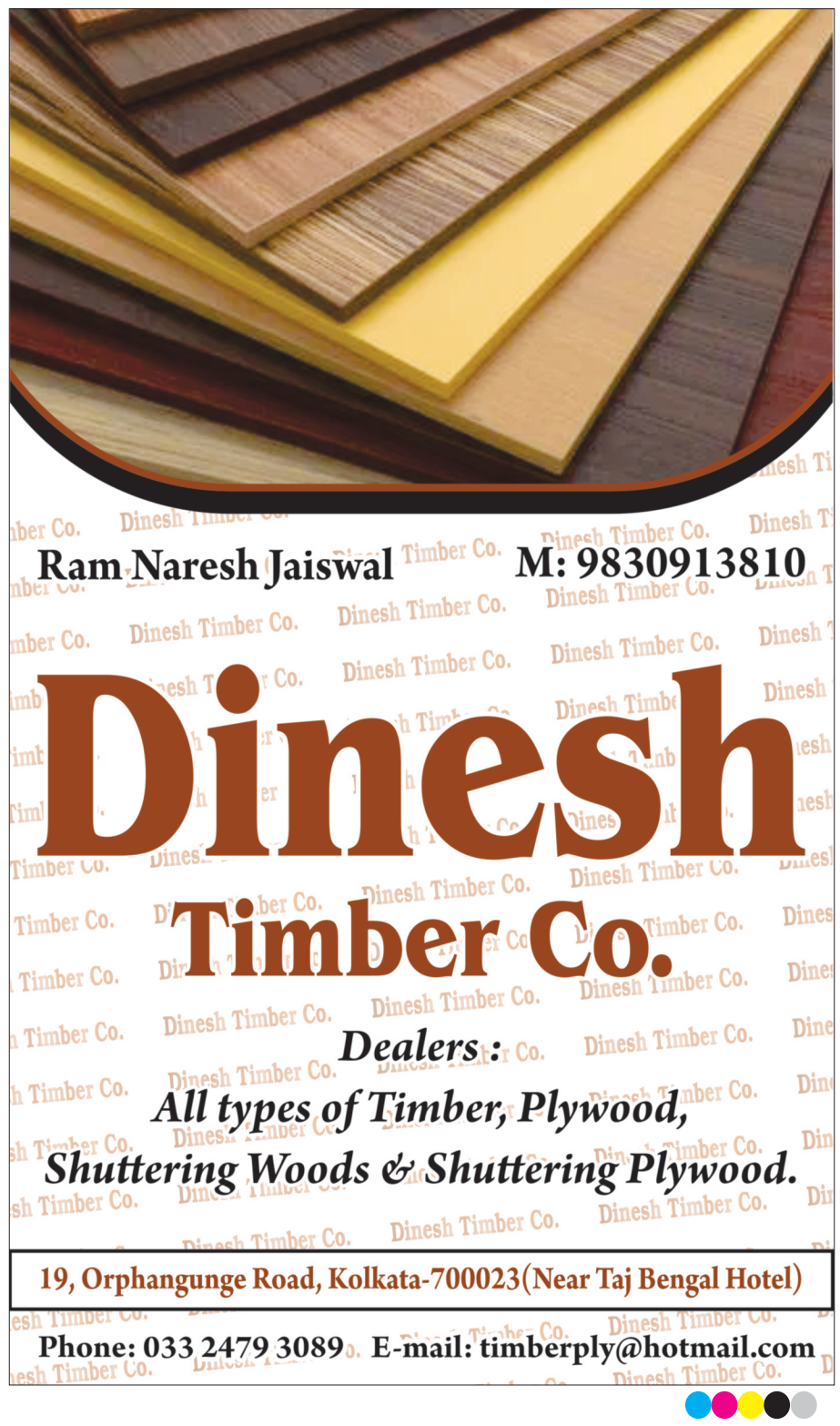

यौन हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशील व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करना, जिसमें 'बलात्कार के प्रयास' की परिभाषा बदल दी गई थी, केवल एक कानूनी सुधार मात्र नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। यह न्यायिक संवेदनशीलता और गंभीर मामलों मे न्यायिक दृष्टि की स्पष्टता की पुन: पुष्टि भी है। सर्वोच्च अदालत ने पॉक्सो एक्ट के साथ ही धारा 376 आईपीसी के तहत आरोप बहाल करके, इस बात पर भी बल दिया कि अपराध के इरादे को, प्रत्यक्ष कृत्य के साथ कमतर नहीं माना जा सकता है। दरअसल, हाईकोर्ट ने इस बाबत जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर तल्ख प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं, जिसे किसी सभ्य समाज की मान्यताओं के प्रतिकूल माना गया था। दरअसल, हाई कोर्ट ने माना था कि एक नाबालिग के उरोज पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी ढीली करना और उसे घसीटकर ले जाने का प्रयास दुराचार की तैयारी थी, न कि बलात्कार का प्रयास, क्योंकि इसमें अपराध की दिशा में कोई सीधा कदम नहीं उठाया गया था। स्वाभाविक रूप से इस तरह की संकीर्ण व्याख्या के खिलाफ समाज में प्रतिक्रिया होनी ही थी। कहीं न कहीं इस तंग व्याख्या से अपराधी के जघन्य इरादे और प्रयास की अवधारणा को कमजोर करने का जोखिम भी था। निस्संदेह, इस तरह की व्याख्या से महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद ही होते। जाहिर है इस तरह की सोच कोई सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह सुखद ही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संकीर्ण व्याख्या वाले मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सार्थक हस्तक्षेप किया है। दरअसल, आपराधिक कानून में, प्रयास तब माना जाता है, जब किसी अपराध की तैयारी उस कृत्य को अंजाम देने में बदल जाती है। जो कि इच्छित अपराध के निकट होती है। इस मामले में आरोप- शारीरिक छेड़छाड़, निर्वस्त्र करने और जबरन घसीटना, यदि सिद्ध हो जाते हैं, तो स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न की ओर एक सुनियोजित कदम की पुष्टि कर देते हैं। जिसे केवल पीड़िता के करुण क्रंदन सुनने वाले प्रत्यक्षदर्शियों के हस्तक्षेप से ही रोका गया।

निस्संदेह, इसके विपरीत मानना यौन हिंसा की वास्तविकताओं और नाबालिगों की असुरक्षा को अनदेखा करना ही होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह फैसला आरोपों की गंभीरता की पुष्टि करता है। ताकि पूर्व सुनवाई में साक्ष्यों की उचित संदर्भ में जांच की जा सके। ऐसे वक्त में जब देश की कई अदालतों के लैंगिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना हो रही थी, यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि कानूनी तर्क को संवैधानिक मूल्यों को बनाये भी रखना चाहिए। निर्विवाद रूप से, जिनका उद्देश्य किसी सभ्य समाज में नागरिकों को आसन्न खतरे से भी बचाना ही होता है। बहरहाल, इस प्रकरण में यह सार्थक हस्तक्षेप इस बात की पुष्टि भी करता है कि कानून बच्चों को न केवल अपराधियों द्वारा अंजाम दिए जा चुके अपराधों से बल्कि भविष्य में आसन्न अपराधों से भी बचाता है। इस प्रकरण के बाद कहा जा सकता है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल न्यायिक जवाबदेही में संतुलन स्थापित किया, बल्कि आखिरकार आम लोगों के विश्वास को भी बहाल किया है। निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया को न्याय के नैसर्गिक नियमों के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। जो देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति आम आदमी के भरोसे को बढ़ाने वाला भी होगा। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जब व्यक्ति समाज में चारों तरफ से व सिस्टम से निराश हो जाता है तो न्याय की चौखट उसकी उम्मीद की अंतिम किरण होती है। यदि वहां से भी संवेदनशील पहल होती न नजर आए तो उसका निराश होना स्वाभाविक ही है। सुप्रीम कोर्ट की इस संवेदनशील पहल ने सही मायने में उस आदमी के भरोसे को ही संबल दिया है। जिसका स्वागत किया जाना जरूरी भी है।

आज का पंचांग

कोलकाता : 20 फरवरी, शुक्रवार, 2026, विक्रम सम्वत् 2082, फाल्गुन शुक्लपक्ष तृतीया, 14:36 तक, नक्षत्र : उत्तरभाद्रपदा, 19:56 तक, योग : साध्य, 18:14 तक, सूर्योदय: 06:06, सूर्यास्त: 17:35, चन्द्रोदय : 07:41, चन्द्रास्त: 20:21, शक सम्वत: 1947 विश्वावसु, सूर्य राशि : कुम्भ, चन्द्र राशि : मीन, राहू काल : 10:24 से 11:50

राशिफल

मेष : प्रोग्रेस हल्की लेकिन मीनिंगफुल होगी। दसवें घर में मंगलदेव की उपस्थिति आपको ऑफिस में सम्मान दिलाएगी। सावधानी से खर्चों को संभालें और लॉन्ग-टर्म स्टेबिलिटी पर ध्यान दें।

वृष : नेटवर्किंग और सहयोग से तरक्की बेहतर होगी। मकर राशि में नौवें घर में मंगलदेव टेक्निकल डिटेल्स को समझने की हिम्मत देते हैं, शुक्र यह पक्का करते हैं कि आपके सीनियर आपको पसंद करें।

मिथुन : अनुशासन और साफ बातचीत से लगातार तरक्की होगी। मीन राशि में चंद्रमा बेहतर नतीजों के लिए बोर्डरूम में इंट्यूशन का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है।

कर्क : नौवें घर के चंद्रमा के गोचर से सीखने और बड़े नजरिये से देखने से करियर में तरक्की बेहतर होगी। मंगलदेव मुश्किल क्लाइंट या कॉम्पिटिटर को डिसिप्लिन के साथ संभालने की हिम्मत देते हैं।

सिंह : अनुशासन से तरक्की लगातार मिलेगी। मकर (छठे घर) में मंगलदेव आपको कॉम्पिटिटर पर बढ़त और डिटेल्ड पेपरवर्क को पूरा करने की हिम्मत देते हैं।

कन्या : कुंभ में सूर्य, बुध और शुक्रदेव की उपस्थिति से टीमवर्क और इनोवेशन से आपकी तरक्की बेहतर होगी। मकर राशि (पांचवें घर) में मंगलदेव प्रोजेक्ट्स को परफेक्ट बनाने के लिए स्टैमिना देंगे।

तुला : अनुशासन और लगातार कोशिश से प्रोग्रेस बेहतर होगी। आज पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन दिन है। हेल्थ या घर से जुड़े खर्चों के बारे में सावधानी से प्लानिंग करें।

वृश्चिक : वसावधानी से प्लानिंग करने और मौजूदा जिम्मेदारियों का रिव्यु करने पर फोकस करें। आठवें घर में बृहस्पति का वक्री होने से आप अपने लोन्स या इंश्योरेंस को रिव्यू करेंगे।

धनु : भविष्य में पहचान के लिए एक मजबूत नींव बनाते हुए आपकी प्रोग्रेस स्थिर रहेगी। चौथे घर में चंद्रदेव आपका ध्यान पर्सनल मामलों की ओर खींच सकते हैं।

मकर : आज ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को फाइनल करने या बिजनेस ट्रैवल करने के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। आपकी राशि में मंगलदेव आपको एक अहम बढ़त दिलाएंगे।

कुम्भ : स्ट्रेटेजी और बिहाइंड-द-सीन्स रिसर्च के जरिए तरक्की लगातार हो रही है। जहां मकर (बारहवें घर) में मंगलदेव शांति से सुधार करने में मदद करेंगे।

मीन : प्लानिंग और बजट रिव्यू पर ध्यान दें। आपके बारहवें घर में ग्रहों के होने से, आपका मन दान या छिपे हुए खर्चों पर हो सकता है। तरक्की अक्सर पर्दे के पीछे रहकर हो रही है।

असमानताओं पर प्रहार, समानता का विस्तार: एक सार्थक पुकार

ललित गर्ग

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज के समय में केवल असमानताओं पर प्रहार एवं समानता के विस्तार की एक सार्थक पुकार का अंतरराष्ट्रीय आयोजन ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का आह्वान है। वर्ष 2026 में यह दिवस विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि विश्व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी संक्रमण, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रूवीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच नई संतुलित व्यवस्था की तलाश में है। इस वर्ष की थीम समावेश को सशक्त बनाना: सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी हो और समावेशन तभी प्रभावी है जब वह न्यायपूर्ण हो। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अवसरों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था की स्थापना का आग्रह करता है जिसमें संसाधनों, अधिकारों और गरिमा का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की समान उपलब्धता नहीं मिलती, तब तक प्रगति अधूरी है। 2026 की थीम विशेष रूप से उन समुदायों की भागीदारी पर बल देती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं- चाहे वे आर्थिक रूप से वंचित हों, सामाजिक रूप से उपेक्षित हों या राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से दूर हों। समावेशन का सशक्तिकरण केवल नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अधिकार है।

आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई कई रूपों में दिखाई देती है। एक ओर तकनीकी क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक श्रम-आधारित रोजगार असुरक्षित होते जा रहे हैं। डिजिटल विभाजन नई सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। ग्रामीण और शहरी, विकसित और विकासशील, पुरुष और महिला, सक्षम और दिव्यांग-इन सबके बीच संसाधनों की असमान पहुंच सामाजिक तनाव को जन्म देती है। ऐसे समय में सामाजिक न्याय का अर्थ है इन अंतरों को पहचानना और उन्हें पाटने के लिए लक्षित, संवेदनशील और पारदर्शी नीतियों का निर्माण करना। सम्मानजनक कार्य की अवधारणा भी सामाजिक न्याय के केंद्र में है। केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा कार्य-संस्कृति बनाना आवश्यक है जिसमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। आर्थिक विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह मानव गरिमा के साथ जुड़ा हो। यदि विकास केवल आंकड़ों में सीमित रह जाए और आम नागरिक के जीवन में राहत न ला सके, तो वह विकास नहीं, केवल विस्तार है।

मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र इस युग की अनिवार्यता बन चुका है। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि संकट किसी भी समाज को अचानक अस्थिर कर सकता है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धजन, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक-इन सभी के लिए संरक्षित ढांचा ही न्यायपूर्ण समाज की नींव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का विचार ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। आज भी सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक पूर्वाग्रहों, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक असमानताओं से भी जुड़ा है।

समकालीन भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा

विश्व सामाजिक न्याय दिवस- 20 फरवरी, 2026

है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और नशा-पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि सामाजिक न्याय विभाजन की राजनीति नहीं, बल्कि समावेशन की नीति के माध्यम से स्थापित हो। संतुष्टिकरण बनाम तुष्टिकरण की अवधारणा इसी दिशा में एक वैचारिक संकेत है, जो समाज को जोड़ने की बात करती है। फिर भी चुनौतियां शेष हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती जीवन-यापन लागत आम नागरिक के लिए वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि जनसंतोष और जनकल्याण सुनिश्चित करना है। यदि नागरिक स्वयं को असुरक्षित, असमान या उपेक्षित अनुभव करें, तो सामाजिक न्याय का आदर्श खोखला प्रतीत होने लगता है।

आज आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व के रूप में देखा जाए। हमने आचरण की पवित्रता एवं पारदर्शिता की बजाय कदाचरण एवं अनैतिकता की कालिमा का लोकतंत्र बना रखा है। ऐसा लगता है कि धनतंत्र एवं सत्तातंत्र ने जनतंत्र को बंदी बना रखा है। हमारी न्याय-व्यवस्था कितनी भी निष्पक्ष, भव्य और प्रभावी हो, फ्रांसिस बेकन ने ठीक कहा था कि 'यह ऐसी न्याय-व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की यंत्रणा के लिये दस अपराधी दोषमुक्त और रिहा हो सकते हैं।' रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था कि 'मनुष्य का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है।' लेकिन हमारे देश के कानून एवं शासन व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता, आम आदमी सजा का जीवन जीने को विवश है। सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक एकता भंग नहीं की जा सकती। शासन और प्रशासन की प्रत्येक नीति का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। यदि शक्ति के स्रोत जनहित में प्रयुक्त न हों, तो वे असंतोष और अविश्वास को जन्म देते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। क्या हमारा लोकतंत्र समानता का लोकतंत्र है या विभेद का? क्या हमारी स्वतंत्रता सबके लिए समान अवसर लेकर आई है या केवल कुछ वर्गों तक सीमित है? क्या हमारी नीतियां पारदर्शिता और नैतिकता पर आधारित हैं या वे जटिलता और असमानता को बढ़ा रही हैं? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोजना ही इस दिवस की सार्थकता है।

सामाजिक न्याय केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेद से ऊपर उठकर यदि नागरिक परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, तो सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ किया जा सकता है। शिक्षा संस्थान, नागरिक संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच-सभी को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा और डिजिटल नवाचार नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन अवसरों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे।

अन्यथा विकास की गाड़ी कुछ लोगों को आगे ले जाएगी और शेष को पीछे छोड़ देगी। समावेशन का सशक्तिकरण इसी असंतुलन को रोकने का प्रयास है। प्रतिदिन कोई न कोई कारण महंगाई को बढ़ाकर हम सबको और धक्का लगा जाता है और कोई न कोई टैक्स, अधिभार हमारी आय को और संकुचित कर जाता है। जानलेवा प्रदूषण ने लोगों की सांसों को बाधित कर दिया, लेकिन हम किसी सम्यक् समाधान की बजाय नये नियम एवं कानून थोप कर जीवन को अधिक जटिल बना रहे हैं। सामाजिक न्याय व्यवस्था तभी सार्थक है जब आम जनता निष्कंटक एवं समस्यामुक्त समानता का जीवन जी सके।

2026 का यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि न्याय और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग सामाजिक न्याय से होकर ही गुजरता है। यदि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ जीवन जी सके, तभी हम कह सकेंगे कि हमने सामाजिक न्याय के आदर्श को साकार किया है। इस तरह सामाजिक न्याय केवल नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि चेतना का प्रश्न है। यह हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों में परिलक्षित होना चाहिए। जब नागरिक और शासन दोनों मिलकर समानता, गरिमा और अवसर की संस्कृति का निर्माण करेंगे, तभी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। समावेश को सशक्त बनाकर और असमानताओं की खाई को पाटकर ही हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, अधिक मानवीय और अधिक स्थायी हो।

-लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

संवेदनशील प्रशासन और संयमित छात्र: संतुलन ही समाधान

आरके जैन अरिजीत

- दूसरी पालियों में समाधान, पहली में जीवन की हार
- परीक्षा से बड़ी है जिंदगी, अंक केवल संकेत हैं, मूल्य नहीं

कभी-कभी बस एक छोटा-सा क्षण पूरी व्यवस्था की आत्मा को बेनकाब कर देता है। घड़ी ने दस मिनट का फासला तय किया- और एक बच्ची परीक्षा कक्ष के बाहर रह गई। वही दस मिनट उसके जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बन गए। नियम अपनी जगह अडिग खड़े रहे, पर जीवन चुपचाप फिसल गया। दूसरी ओर, एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र कम पड़े तो उसी तंत्र ने नियमों को मोड़कर दो पालियों में परीक्षा करा दी। यही विरोधाभास हमारे समय की नंगी सच्चाई है-जहाँ सुविधा हो वहाँ नियम लचीले, और जहाँ करुणा चाहिए वहाँ वे पत्थर बनकर गिरते हैं।

दस मिनट की देरी पर दरवाज़ा बंद कर देना नियम की कठोरता नहीं, संवेदना की विफलता है। परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभा की जाँच है, न कि घड़ी की सुइयों की पूजा। यदि चाहा जाता तो कोई व्यावहारिक रास्ता निकाला जा सकता था-जैसा अन्य परिस्थितियों में निकाला भी गया। पर यहाँ नियमों की दीवार ऊँची कर दी गई और मानवीय विवेक को बाहर छोड़ दिया गया। परिणाम केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं रहा, वह एक असहनीय त्रासदी में बदल गया। प्रश्न नियमों के अस्तित्व का नहीं, उनमें जीवित मनुष्यता की उपस्थिति का है। क्या व्यवस्था इतनी यांत्रिक हो चुकी है कि उसे परिस्थितियों की धड़कन सुनाई ही नहीं देती?

इसी क्रम में दूसरी घटना ने तंत्र का दूसरा चेहरा भी दिखाया। जब प्रश्नपत्र कम पड़ गए और व्यवस्था की अपनी भूल उजागर हुई, तो तुरंत समाधान तलाश लिया गया। दो पालियाँ बनीं, प्रतियाँ तैयार हुईं, समय-सारिणी बदली-और परीक्षा पूरी करा दी गई। यहाँ नियमों को मोड़ना संभव था, क्योंकि आवश्यकता थी। यही विरोधाभास सबसे चुभता है-जहाँ सिस्टम की असुविधा हो, वहाँ लचीलापन; जहाँ छात्र की मजबूरी हो, वहाँ कठोरता क्यों? क्या नियम केवल नीचे की ओर सख्त और ऊपर की ओर नरम होते हैं? क्या करुणा का पैमाना भी पद और अधिकार देखकर बदल जाता है?

पर इस पूरी पीड़ा का एक और पक्ष भी है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं होती। अंक केवल भविष्य की दिशा तय करते हैं, अस्तित्व की कीमत नहीं। देर हो जाए तो अगला अवसर मिलता है, अगला प्रयास संभव है, अगला वर्ष भी आता है। पर यदि जीवन का पन्ना ही फाड़ दिया जाए, तो उसे कोई परिणाम फिर नहीं जोड़ सकता। क्षणिक आवेग में उठाया गया चरम कदम समस्या का समाधान नहीं, परिवार के लिए आजीवन घाव बन जाता है। हमें यह समझना और समझाना होगा कि असफलता अंत नहीं, अनुभव है; ठोकर हार नहीं, आगे बढ़ने की तैयारी है।

हमारे समाज ने परीक्षा को उपलब्धि से आगे बढ़ाकर प्रतिष्ठा और पहचान का पैमाना बना दिया है। अंक अब केवल परिणाम नहीं रहे, वे मानो सम्मान का प्रमाणपत्र बन गए हैं। माता-पिता की आकांक्षाएँ, रिश्तेदारों की तुलना और सोशल मीडिया की चकाचौंध-ये सब मिलकर एक कोमल मन पर ऐसा दबाव रचते हैं, जो दिखाई नहीं देता पर भीतर गहराई तक चुभता है। ऐसे माहौल में दस मिनट की देरी महज़ समय का अंतर नहीं रह जाती; वह मानो सपनों के ढह जाने का प्रतीक बन जाती है। यहीं परिवार और विद्यालय की असली भूमिका शुरू होती है। बच्चों को सिखाना होगा कि जीवन की कीमत किसी परिणाम से कहीं अधिक है। परीक्षा एक अवसर है, अस्तित्व का अंतिम सत्य नहीं।

प्रशासन की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। नियम अनुशासन बनाए रखने के लिए होते हैं, पर उनका उद्देश्य मनुष्यों की रक्षा करना है, उन्हें तोड़ना नहीं। यदि कोई नियम ऐसी स्थिति पैदा करे जहाँ जीवन ही संकट में पड़ जाए, तो उसके स्वरूप पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। हर परीक्षा केंद्र पर मानवीय विवेक की एक खिड़की खुली रहनी चाहिए-ऐसी व्यवस्था, जहाँ आपात स्थिति में समाधान खोजा जा सके। जब तकनीकी त्रुटियों पर तत्काल विकल्प संभव हैं, तो कुछ मिनट की देरी पर संवेदना असंभव क्यों प्रतीत होती है? प्रशासनिक दक्षता के साथ संवेदनशीलता भी अनिवार्य प्रशिक्षण का हिस्सा बननी चाहिए।

छात्रों के लिए यह घटना एक चेतावनी भी है और एक सीख भी। समयपालन कोई औपचारिक नियम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व की रीढ़ है; अनुशासन ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। परीक्षा के दिन तैयारी केवल पाठ्यक्रम की नहीं, परिस्थिति की भी होनी चाहिए-समय से पहुँचना, विकल्प सोचकर चलना, जोखिम से बचना। किंतु यदि कभी चूक हो जाए, तो उसे जीवन की हार का नाम न दें। सच्चा साहस गिरकर फिर खड़े होने में है, न कि एक ठोकर को अंतिम सत्य मान लेने में। असफलता से जूझना परिपक्वता है; क्षणिक आवेग में स्वयं को ही दंडित कर देना नहीं। जीवन एक लंबी दौड़ है-एक मोड़ फिसलन भरा हो सकता है, पर वह पूरी मंज़िल को निगल नहीं सकता।

यह घटना हमें एक कठोर सत्य से रूबरू कराती है-संतुलन ही व्यवस्था और जीवन, दोनों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नियम हों, पर उनमें मानवता की धड़कन भी हो; अनुशासन हो, पर उसके साथ समझ और संवेदना भी। उतना ही जरूरी है कि विद्यार्थी भी क्षणिक आघात को अंतिम फैसला न बनने दें। समाधान किसी एक पक्ष की कठोरता में नहीं, दोनों के सामंजस्य में छिपा है। जब प्रशासन विवेकशील हो और युवा संयमित, तभी त्रासदियों के रास्ते बंद होते हैं। यदि व्यवस्था पत्थर न बने और छात्र आवेग के बजाय साहस चुनें, तो अनेक घरों की रोशनी बच सकती है। परीक्षा कक्ष का दरवाज़ा समय पर बंद हो सकता है, पर जीवन का द्वार कभी बंद नहीं होना चाहिए- और उसे खुला रखना ही समाज, सिस्टम और छात्र, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

विदेश की खबरें

प्रधानमंत्री मोदी की तेल अवीव यात्रा से पहले भारत-इजराइल ने रक्षा सहयोग के लिए एक और करार किया

तेल अवीव : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इसी महीने के आखिर में होने वाली इजराइल यात्रा से पहले, भारत और इजराइल ने रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने और भविष्य की संगोष्ठियों तथा सहकारी पहलों सहित चल रही संयुक्त गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय (आईएमओडी) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय (एसआईबीएटी) ने भारत और इजराइल के प्रमुख रक्षा उद्योगों के बीच बैठकों की सुविधा प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। आईएमओडी द्वारा जारी बयान में बताया गया कि एसआईबीएटी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एसआईडीएम) और भारत के रक्षा मंत्रालय के सहयोग से इस सप्ताह अग्रणी भारतीय और इजराइली रक्षा कंपनियों के बीच एक संगोष्ठी और बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) बैठकों का आयोजन किया।

ब्रिटेन की पुलिस ने कदाचार की जांच के सिलसिले में चार्ल्स तृतीय के भाई एंड्रयू को गिरफ्तार किया

लंदन : ब्रिटेन की पुलिस ने बृहस्पतिवार को महाराजा चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर को सार्वजनिक पद पर रहते हुए कदाचार के संदेह में गिरफ्तार किया है। उन पर यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन के साथ संबंध रखना का आरोप भी है। टेम्स वैली पुलिस ने कहा कि बर्कशायर और नॉरफॉक में पूर्व प्रिंस से जुड़े ठिकानों पर तलाश अभियान जारी हैं, जबकि वह पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति का नाम नहीं बताया है, लेकिन ऐसी खबर है कि इस गिरफ्तारी में एंड्रयू शामिल हैं। एंड्रयू का बृहस्पतिवार को जन्मदिन भी है और आज वह 66 वर्ष के हो गये। टेम्स वैली पुलिस के सहायक मुख्य कांस्टेबल ओलिवर राइट ने कहा, ''गहन मूल्यांकन के बाद, हमने सार्वजनिक पद पर रहते हुए कदाचार के इस आरोप की जांच शुरू कर दी है।

वर्ग पहेली नं. 3357

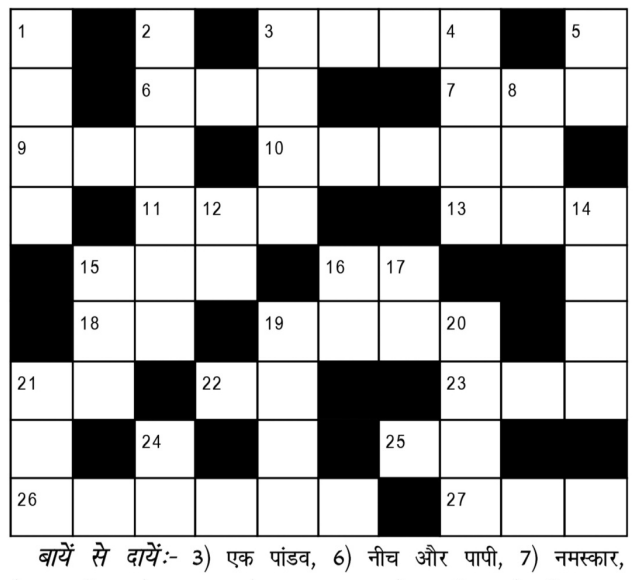

बायें से दायें:- 3) एक पांडव, 6) नीच और पापी, 7) नमस्कार, 9) आलसी, 10) मल्ल, 11) एक फल, 13) झक्की, 15) जी आना, 16) तदुपरान्त 18) रक्तवर्णीय, 19) गलना, 21) पर्यन्त, 22) इक्का-दुक्का, 23) हिसाब, 25) वैरी, 26) दयनीय, 27) व्यवहार; आचरण.

ऊपर से नीचे:- 1) एक भारतीय शहर, 2) धूमधाम, 3) नजदीकी, 4) दंडस्वरूप अरण्य में रहना, 5) लिए, 8) चिंतन, 12) घूँट लेना,14) प्रशंसा गीत, 15) चालबाज़, 16) एक हिंस्र पशु, 17) व्यवस्थित समूह, 19) अवनति, 20) एक भारतीय शहर, 21) थोड़ा, 24) घिन. *(उत्तर: अगले अंक में)*

पिछली पहेली का उत्तर

क	व	च	■	■	अ	ग	ल	■	घ
ट	■	म	ज	बू	र	■	ल	ह	मा
क	ल	क	ल	■	मा	वा	■	■	सा
■	■	दा	■	आ	न	न	फ़ा	न	न
अ	स	र	दा	र	■	र	■	ट	■
ग्र	■	■	■	ती	र	■	अ	ना	स्था
ज	न्म	दा	ता	■	त	मा	म	■	■
■	■	स	ब	ल	■	ख	ल	ब	ली
सु	भी	ता	■	ब	द	न	■	ला	खा

सुडोकू-पहेली-3315

9	1	2		3				8
		3			2			6
	2	7			4	3	5	
					3			
				9	5		7	
				7				1
						8		
		4		6	9			

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरना आवश्यक है। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है।

••••

आड़ी और खड़ी में एवं 3-3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान जरूर रखें।

सूडोकू पहेली - 3314 का उत्तर

6	2	8	9	7	4	5	1	3
3	1	7	6	5	8	4	2	9
9	5	4	2	1	3	8	6	7
4	6	5	7	2	1	3	9	8
7	9	1	3	8	5	6	4	2
8	3	2	4	9	6	1	7	5
1	7	6	8	3	2	9	5	4
5	8	9	1	4	7	2	3	6
2	4	3	5	6	9	7	8	1

मुख्यमंत्री ममता ने श्रीरामकृष्ण परमहंस की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

दक्षिणेश्वर-कामारपुकुर-जयरामबाटी के विकास कार्यों का उल्लेख

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर युगावतार श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जन्मतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम अर्पित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की भूमि उनके आविर्भाव से धन्य हुई है और उनकी अमृतवाणी व सर्वधर्म समन्वय का आदर्श आज भी समाज के लिए आलोकस्तंभ है। मुख्यमंत्री ने 'जितने मत, उतने पथ' के शाश्वत संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि 'मानव सेवा ही ईश्वर सेवा' – इस शिक्षा को उन्होंने जीवन भर अपनाया है और आगे

भी इसी प्रेरणा के साथ जनसेवा करती रहेंगी।

पोस्ट में ममता ने बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस से जुड़े तीर्थस्थलों के विकास के लिए राज्य सरकार ने व्यापक कार्य किए हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर परिसर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने के लिए 'रानी रासमणि स्काईवॉक', मंदिर परिसर की आकर्षक प्रकाश-सज्जा, सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार और नया जेटी बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन को काली मंदिर की तर्ज पर सजाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीरामकृष्ण की जन्मभूमि कामारपुकुर और मां शारदा की जन्मभूमि जयरामबाटी के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए 'जयरामबाटी-कामारपुकुर डेवलपमेंट बोर्ड' का गठन किया गया और अब तक बोर्ड को 10 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इन पवित्र तीर्थ क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास में पहले ही लगभग 80 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से सड़क संपर्क बेहतर किया गया है और 5.87 करोड़ रुपये से पर्यटन अवसंरचना विकसित की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए कामारपुकुर ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन और ग्रामीण अस्पताल में विशेष हेल्थ यूनिट की स्थापना की गई है। यात्रियों व पर्यटकों की सुविधा के लिए करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बस स्टैंड और एक इको-टूरिज्म पार्क भी बनाया गया है। इसके अलावा, कामारपुकुर मिशन में हॉस्टल भवन निर्माण तथा जयरामबाटी के मातृमंदिर के जीर्णोद्धार की पहल की गई है। रामकृष्ण मठ एवं मिशन के अनुरोध पर भक्तों की सुविधा के लिए पांच मंजिला गेस्ट हाउस और प्रसाद वितरण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, बड़े क्षेत्र में ओपन पार्किंग जोन विकसित किया जा रहा है, जिस पर सरकार लगभग 5.77 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कामारपुकुर स्थित रामकृष्ण मठ एवं मिशन परिसर में पेयजल समस्या के समाधान के लिए पहले ही पाइपलाइन और नलकूप लगाए गए थे। अब व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नया गहरा नलकूप और पंप हाउस का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। ममता ने अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार श्री रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा से जुड़े इन पवित्र स्थलों के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

बंगाल के लोग पसंद का भोजन करने को स्वतंत्र : समिक भट्टाचार्य

कहा... 'भाजपा केवल खुले में बीफ की बिक्री के खिलाफ'

कोलकाता, समाज्ञा : बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के 'खुले में मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध' संबंधी आरोपों को लेकर जारी राजनीतिक तकरार के बीच, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य के लोग अपनी पसंद का भोजन करने के लिए स्वतंत्र हैं और पार्टी केवल खुले में बीफ की बिक्री के खिलाफ है। भट्टाचार्य ने पड़ोसी राज्य बिहार में खुलेआम मछली और मांस की बिक्री पर प्रस्तावित प्रतिबंध लगाने संबंधी तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बंगाल के लोग जो चाहेंगे, वही खाएंगे। बंगाल में मछली और मांस मिलता रहेगा। बिहार के निर्देश पर विस्तार से बात करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा ने इस तरह के किसी भी व्यापक प्रतिबंध का प्रस्ताव

नहीं रखा था। उन्होंने कहा कि वे कभी ऐसी बात कह ही नहीं सकते। क्यों कहें? कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस इन टिप्पणियों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई प्रतिबंध लागू होता है तो बिहार या पश्चिम बंगाल में कोई भी इसका पालन नहीं करेगा और फिलहाल ऐसा कोई प्रतिबंध मौजूद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा का रुख केवल बीफ की खुलेआम बिक्री का विरोध करने तक ही सीमित है।

चुनाव से पहले भाजपा को झटका, बागी विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा तृणमूल कांग्रेस में शामिल

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले, भाजपा के बागी विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा गुरुवार को राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गये। कार्सियांग विधानसभा सीट से विधायक शर्मा तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु और उद्योग मंत्री शशि पांजा ने तृणमूल में उनका स्वागत किया। बता दें कि बिष्णु प्रसाद शर्मा के जाने से विधानसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या घटकर 64 हो गई है। तृणमूल में शामिल होने के बाद, बिष्णु प्रसाद शर्मा ने कहा कि वह तृणमूल में टिकट के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति के साथ जुड़ने

के लिए शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक आजाद पंछी हूं। मैंने कार्सियांग की जनता के जनादेश का अनादर नहीं किया है। कुछ लोग मेरी आलोचना करेंगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। भाजपा पर गोरखाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि गोरखा लोग 17 वर्षों से अंधेरे में जी रहे हैं। भाजपा उन्हें मशाल दिखाकर उसे सूरज बता रही है। क्या मुझे अपने मतदाताओं के साथ जुमला राजनीति खेलनी चाहिए? भाजपा गोरखाओं के लिए कुछ नहीं करेगी। केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के लिए आवंटित धनराशि को रोक दिया गया है। शर्मा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 'विकास मॉडल' के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे गोरखा भाइयों और बहनों ने चुना था, लेकिन मैं उनके लिए काम नहीं कर पाया। भाजपा ने वादे तो किए लेकिन कुछ नहीं किया। जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ।

चुनाव से पहले राज्य पुलिस में फिर फेरबदल, तीन जिलों के एसपी समेत चार आईपीएस अधिकारी का तबादला

कोलकाता, समाज्ञा : विधानसभा चुनाव से पहले राज्य पुलिस में एक और फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने गुरुवार को तीन जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) सहित चार आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, तबादला सूची में अलीपुरद्वार, बसीरहाट और जंगीपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और राज्य खुफिया ब्यूरो (आईबी) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का नाम शामिल हैं। अलीपुरद्वार जिले के एसपी खंडभले उमेश गणपत का तबादला उत्तर बंगाल खुफिया ब्यूरो (आईबी) के एसएस के पद पर कर दिया गया है। उनकी जगह जंगीपुर पुलिस जिले के एसपी रहे अमित कुमार साव को अलीपुरद्वार का नया एसपी नियुक्त किया गया है। डॉ. हुसैन मेहदी रहमान को बसीरहाट पुलिस जिले के एसपी पद से हटाकर उन्हें जंगीपुर पुलिस जिले का एसपी बनाया गया है। आईबी के एसएस रहे आरिश बिलाल को बसीरहाट पुलिस जिले का नया एसपी नियुक्त किया गया है।

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना संख्या : ईएल/एचडब्ल्यूएच/25/21 (सूचना)/742, दिनांक 18.02.2026, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, हावड़ा, नई डीआरएम बिल्डिंग, रेल म्यूजियम के पास, हावड़ा-711101 द्वारा निम्नलिखित विद्युत कार्यों के लिए ओपन ई-टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं : **क्रम सं. 1, निविदा संख्या: ईएल-एचडब्ल्यूएच-25-21-3558, कार्य का नाम :** "एईएन/नबद्वीप धाम के अधीन रेलवे के रिलीविंग गर्डर द्वारा लेवल क्रॉसिंग गेट नं. 5/3 के स्थान पर नए सीमित ऊँचाई के सबवे का निर्माण" के संबंध में विद्युत (सामान्य) कार्य। **निविदा मूल्य :** रु. 9,25,614/-, **बोली सुरक्षा (जमा धन राशि):** रु. 18,500/-, **पूर्णता अवधि:** 180 दिन। **क्रम सं. 2, निविदा संख्या: ईएल-एचडब्ल्यूएच-25-21-3581, कार्य का नाम :** "हावड़ा मेट्रो की ओर से हावड़ा स्टेशन तक प्रवेश/निकास द्वारों की व्यवस्था, हावड़ा स्टेशन के पुराने परिसर भवन, पुराने परिसर से नए परिसर में पैसेंजर शेड के सुदृढ़ीकरण के बाद प्लेटफॉर्म-12 के ओआरएच पर खुली छत वाले स्थान के पास सीआईटी/आउटडोर कार्यालय को स्थानांतरित करके सीआईटी आउटडोर कार्यालय के स्थान पर प्लेटफॉर्म-12 में डीलक्स शौचालय, सड़क का विकास, यात्रियों को जानकारी के लिए पर्याप्त रोशनी और वीडियो वॉल के प्रावधान" के संबंध में विद्युत (सामान्य) कार्य। **निविदा मूल्य :** रु. 29,15,821/-, **बोली सुरक्षा (जमा धन राशि):** रु. 58,300/-, **पूर्णता अवधि:** 180 दिन। **क्रम सं. 3, निविदा संख्या: ईएल-एचडब्ल्यूएच-25-21-3564, कार्य का नाम :** "एईएन/आजिमगंज के अधीन रेलवे के रिलीविंग गर्डर द्वारा लेवल क्रॉसिंग गेट नं. 24ए/4(ई) के स्थान पर नए सीमित ऊँचाई के सबवे का निर्माण" के संबंध में विद्युत (सामान्य) कार्य। **निविदा मूल्य :** रु. 9,25,614/-, **बोली सुरक्षा (जमा धन राशि):** रु. 18,500/-, **पूर्णता अवधि:** 180 दिन। **क्रम सं. 4, निविदा संख्या: ईएल-एचडब्ल्यूएच-25-21-3551, कार्य का नाम :** "एईएन/नबद्वीप धाम के अधीन रेलवे के रिलीविंग गर्डर द्वारा लेवल क्रॉसिंग गेट नं. 7/सी के स्थान पर नए सीमित ऊँचाई के सबवे का निर्माण" के संबंध में विद्युत (सामान्य) कार्य। **निविदा मूल्य :** रु. 9,25,614/-, **बोली सुरक्षा (जमा धन राशि):** रु. 18,500/-, **पूर्णता अवधि:** 180 दिन। **क्रम सं. 5, निविदा संख्या: ईएल-एचडब्ल्यूएच-25-21-3565, कार्य का नाम :** "एईएन/आजिमगंज के अधीन रेलवे के रिलीविंग गर्डर द्वारा लेवल क्रॉसिंग गेट नं. 24ए/12(ई) के स्थान पर नए सीमित ऊँचाई के सबवे का निर्माण" के संबंध में विद्युत (सामान्य) कार्य। **निविदा मूल्य :** रु. 9,25,614/-, **बोली सुरक्षा (जमा धन राशि):** रु. 18,500/-, **पूर्णता अवधि:** 180 दिन। **समापन तिथि एवं समय:** दिनांक 12.03.2026 को 15.00 बजे। यदि किसी कारणवश उपर्युक्त समापन तिथि को अवकाश/ बंद/हड़ताल घोषित किया जाता है, तो ऑनलाइन निविदा जमा करने की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आईआरईपीएस वेबसाइट पर समापन तिथि और समय के बाद कोई निविदा जमा नहीं की जा सकती। हालांकि, निविदाओं का ऑनलाइन उद्घाटन समापन तिथि के बाद किसी भी सुविधाजनक दिन किया जा सकता है। निविदा का पूर्ण विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदाकारों से अनुरोध है कि उपरोक्त वेबसाइट पर अपनी निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करें। HWH-635/2025-26

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/(सामान्य), पूर्व रेलवे, सियालदह, दूसरी मंजिल, रिमोट कंट्रोल बिल्डिंग, कोलकाता-700014 द्वारा निम्नवर्णित कार्यों के सिलसिले में निम्नलिखित ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं: **क्रम सं. 1, निविदा संख्या : ईएलईजी-ओटी-1294-2025-26, दिनांक : 17.02.2026, कार्य का विवरण:** वरिष्ठ डीईएन/III/सियालदह के कार्यक्षेत्र में सीमेंट कंक्रीटिंग के साथ माझदिया, बानपुर, गंगनापुर, बादकुल्ला, हबीबपुर, फुलिया, बाथना कृत्तिबास हाल्ट, पगलाचंडी, न्यू बलरामपुर हाल्ट, कासिमबाजार, मुर्शिदाबाद, जियागंज, सुबर्णमृगी, भगवानगोला, पीरतला, कृष्णपुर, लालगोला (कुल =28 अदद) में प्लेटफॉर्म को ऊँचा करना एवं सभी अन्य सहायक कार्य। **निविदा मूल्य:** रु. 1,41,19,474/-, **बयाना राशि:** रु. 2,20,600/-, **क्रम सं. 2, निविदा संख्या : ईएलईजी-ओटी-1300-2025-26, दिनांक : 17.02.2026, कार्य का विवरण:** वरिष्ठ डीईएन/III/सियालदह के अधीन सियालदह मंडल में विभिन्न स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज पर शेड का प्रावधान एवं सभी अन्य सहायक कार्य। **निविदा मूल्य:** रु. 65,36,663/-, **बयाना राशि:** रु. 1,30,700/-, **समापन अवधि:** 12 माह (क्रम सं. 1 एवं 2 हेतु)। **बोली प्रारंभ होने की तिथि:** दिनांक 25.02.2026 (क्रम सं. 1 एवं 2 हेतु)। **निविदा बंद होने की तिथि और समय:** दिनांक 11.03.2026 को 14.00 बजे (क्रम सं. 1 एवं 2 हेतु)। निविदा सूचना एवं समय-समय पर जारी संशोधनी का विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध हैं। SDAH-406/2025-26

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

निविदा सं.: एसडीएसटीई-एलएचएस-एलसीजी-41-16-सी-ई, दिनांक: 17.02.2026, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, हावड़ा, नई डीआरएम बिल्डिंग, रेल म्यूजियम के पास, हावड़ा-711101 द्वारा **निविदा सं.: एसडीएसटीई-एलएचएस-एलसीजी-41-16-सी-ई** के प्रतिपक्ष निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। बोलीदाता केवल अंतिम तिथि और समय तक अपनी मूल/संशोधित बोली जमा कर पाएंगे। इस निविदा के लिए मैनुअल प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है एवं मैनुअल प्रस्ताव प्राप्त होने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। **कार्य का नाम:** हावड़ा मंडल-निम्नलिखित के संबंध में सिग्नलिंग कार्य-शेड्यूल ए1-एईएन/बैण्डेल के तहत रेलवे के रिलीविंग गर्डर द्वारा लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 41 के बदले नए सीमित ऊँचाई के सबवे के निर्माण के लिए सिग्नलिंग लागत। शेड्यूल ए2-एईएन/बैण्डेल के तहत रेलवे के रिलीविंग गर्डर द्वारा लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 41 के बदले नए सीमित ऊँचाई के सबवे के निर्माण के लिए टेलीकॉम लागत। शेड्यूल बी1-एईएन/कटवा के तहत बी.के सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 16/सी/ई के बदले नए सीमित ऊँचाई के सबवे के निर्माण के लिए सिग्नलिंग लागत। शेड्यूल बी2-एईएन/कटवा के तहत बी.के सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 16/सी/ई के बदले नए सीमित ऊँचाई के सबवे के निर्माण के लिए टेलीकॉम्यूनिकेशन लागत। **बोली प्रणाली :** एकल पैकेट। **विज्ञापित मूल्य:** रु. 2,65,97,689.82, **बयाना राशि/बोली प्रतिभूति:** रु. 2,83,000/-, **निविदा कागजात का मूल्य:** रु. 0.00, **समापन अवधि:** 12 माह। **प्रस्ताव की वैधता :** 60 दिन। **निविदा अपलोड करने की तिथि और समय:** दिनांक 17.02.2026 को 18.20 बजे। **बोली प्रारंभ होने की तिथि:** दिनांक 27.02.2026, **निविदा की अंतिम तिथि और समय:** दिनांक 13.03.2026 को 15.00 बजे। निविदा का विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। HWH-633/2025-26

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

तृणमूल नेता ने पार्टी विधायक पर हत्या के प्रयास का लगाया आरोप, थाने में शिकायत दर्ज

कोलकाता, समाज्ञा : दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ क्षेत्र के प्रमुख तृणमूल कांग्रेस नेता कैजर अहमद ने गुरुवार को अपनी ही पार्टी के कैनिंग (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र के विधायक सौकत मोल्ला के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। भांगड़ थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में अहमद ने आरोप लगाया है कि मोल्ला ने उन्हें मरवाने के लिए सुपारी किलर को नियुक्त किया। उन्होंने लिखित शिकायत के साथ ईमेल के माध्यम से भी पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया और मांग की कि उनके आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। अहमद ने विशेष रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रासंगिक धाराओं, जिनमें धारा 173

भी शामिल है, के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों की जान को खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक सौकत मोल्ला या उनके किसी निकट सहयोगी की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी।

उम्मीदवारी के लिए कम आवेदन से चिंतित राज्य भाजपा, विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी हलचल

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक ओर तृणमूल कांग्रेस सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है। हालांकि चुनाव से पहले भाजपा खेमे में नई चिंता उभरती दिख रही है। सूत्रों के अनुसार, इस बार भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनने के लिए अपेक्षित संख्या में आवेदन नहीं मिल रहे हैं। हर चुनाव की तरह पार्टी कार्यालयों में उम्मीदवार बनने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन बॉक्स रखा गया है, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में इस बार प्रतिक्रिया काफी कम बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, लगभग एक माह बीतने के बाद भी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए प्रत्याशी बनने हेतु एक हजार से भी कम आवेदन पत्र जमा हुए हैं। जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले यही संख्या 17 हजार से अधिक थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 20 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे। ऐसे में पार्टी के भीतर यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस बार उम्मीदवार बनने को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह कम है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस विषय पर कोई बयान सामने नहीं आया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया और पार्टी की संगठनात्मक स्थिति को लेकर आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी।

राज्य के दो विश्वविद्यालयों में नए स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति

कोलकाता : राज्य के दो विश्वविद्यालयों में नए स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति की गई है। बारासात राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नए स्थायी कुलपति के रूप में प्रोफेसर देवव्रत मित्र ने पदभार ग्रहण किया है। वहीं कूचबिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय की नई स्थायी कुलपति प्रोफेसर संचारी राय मुखोपाध्याय बनी हैं। आचार्य एवं राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने दोनों नियुक्तियों पर हस्ताक्षर किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नई नियुक्तियों के साथ ही दोनों विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

आनंदपुर अग्निकांड : 24 दिन बाद भी नहीं हुई मृतकों की पहचान

अभी तक केवल 18 शवों की हो सकी हैं पहचान, अपनों के शव के इंतजार में कई परिवार

कोलकाता, समाज्ञा

आनंदपुर के भीषण अग्निकांड को 24 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी मृतक की आधिकारिक पहचान नहीं हो सकी है। परिजनों को अपने प्रियजनों के अवशेष तक नहीं मिले हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से घोषित 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता 27 परिवारों के हाथों में पहुंच चुकी है। बिना सरकारी पुष्टि के मुआवजा दिए जाने से परिजनों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने घटना के बाद मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी। जली हुई गोदामों में से एक 'वाओ मोमो' कंपनी की भी थी। कंपनी ने अपने तीन कर्मचारियों के परिवारों को अलग से आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया था। हाल ही में, प्रभावित परिवारों को 10-10 लाख रुपये के चेक सौंपे गए। कहीं जिला प्रशासन ने चेक दिए तो कहीं स्थानीय नेताओं के माध्यम से यह राशि वितरित की गई। हालांकि, मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि से पहले मुआवजा देने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अब भी बरामद किए गए अवशेषों की डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

फोरेंसिक विभाग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस प्रकार की डीएनए जांच में अतिरिक्त समय लगता है। अवशेषों की स्थिति ऐसी है कि बिना डीएनए परीक्षण के पहचान संभव नहीं है। मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जली हुई गोदाम के मालिक गंगाधर के अलावा पुलिस ने 'वाओ मोमो' गोदाम के मैनेजर मनोरंजन शिट और डिप्टी मैनेजर राजा चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया है। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। आग से केवल दो लोग ही जान बचाकर निकल पाए थे, जिनसे भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। कंपनी के दफ्तर के मालिक और अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ कर बयान दर्ज किए गए हैं। डीएनए रिपोर्ट कब आएगी, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं है।

चुनाव से पहले भाजपा ने बंगाल में महाजंगलराज का किया दावा, ई-पुस्तिका जारी की

❑ **राज्य की आर्थिक बदहाली, कर्ज और कानून-व्यवस्था पर चिंता**

कोलकाता, समाज्ञा : विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा ने राज्य में व्याप्त कथित अराजकता, भ्रष्टाचार और गहराते आर्थिक संकट पर ममता सरकार को घेरते हुए एक ई- पुस्तिका जारी की है। 'आधारेर कोतो कोथा' नामक शीर्षक से जारी इस पुस्तिका में राज्य में पिछले 15 वर्षों से ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल को महाजंगलराज करार देते हुए आर्थिक बदहाली सहित कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ आदि को उजागर किया गया है। 34 पन्नों के इस किताब में भाजपा ने राज्य की वर्तमान स्थिति को गहरे संकट में बताया है। राज्य भाजपा के मीडिया समन्वयक बिमल शंकर नंदा ने बताया कि ई पुस्तिका का शीर्षक 'आधारेर कोतो कोथा' का मतलब अंधेरे की कहानियां हैं। पुस्तिका में राज्य की चरमराती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताते हुए दावा किया गया है कि तृणमूल के 15 साल के गलत शासन की वजह से बंगाल आज गहरे संकट में है और कर्ज में डूबा है। पार्टी ने आंकड़े पेश करते हुए दावा किया है कि पिछले 15 सालों में राज्य का कर्ज का बोझ लगभग चार गुना (393 प्रतिशत) बढ़ गया है। वर्ष 2011-12 में, राज्य का कुल कर्ज 2.07 लाख करोड़ रुपये था। मई, 2011 में तृणमूल के शासन में आने के बाद से 2026-27 में कर्ज बढ़कर लगभग 8.16 लाख करोड़ होने का अनुमान है। पार्टी ने दावा किया कि 15 सालों में, प्रति व्यक्ति कर्ज 22,570 रुपये से बढ़कर 81,165 रुपये हो गया है। हर परिवार पर औसतन लगभग 3.25 लाख रुपये का कर्ज का बोझ है। पुस्तिका के अनुसार, आज बंगाल में जन्म लेने वाला हर बच्चा अपने सिर पर 81,165 रुपये का कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। भाजपा ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में अब तक 6,668 कंपनियां बंगाल छोड़कर महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में जा चुकी हैं। बंगाल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत 41 प्रतिशत कम है, जिसके कारण राज्य राष्ट्रीय रैंकिंग में 24वें स्थान पर पिछड़ गया है। राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए ममता सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट को एक तमाशा बताते हुए पुस्तिका में कहा गया है कि घोषित परियोजनाओं में से केवल तीन प्रतिशत ही धरातल पर उतरी हैं।

❑ **कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार का भी जिक्र**

पुस्तिका में राज्य में व्याप्त सिंडिकेट राज, चुनावी हिंसा और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का भी जिक्र किया गया है। साथ ही, शिक्षकों और अन्य भर्ती में हुए हजारों करोड़ों के भ्रष्टाचार और राज्य कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (डीए) के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। भाजपा ने लोगों से परिवर्तन की अपील करते हुए संकल्प जताया कि इस महाजंगलराज को समाप्त कर बंगाल में पारदर्शिता और कानून का शासन बहाल किया जाए।

आद्रा मंडल के तहत कैटरिंग/एमपीएस अनुबंध के लिए ई-नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, आद्रा मंडल, दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा कैटरिंग/एमपीएस के लिए निम्नानुसार ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है: ● **कैटेगरी : कैटरिंग, नीलामी कैटलॉग सं. : सीएटीजी46, लॉट सं./कैटेगरी :** i) सीएटीजी-एडीआरए-बीयूआरएन-जीएमयू-47-26-1 (कैटरिंग-जनरल माइनर यूनिट (जीएमयू)), **नीलामी शुरू (सभी लॉट) :** दिनांक 06.03.2026, 12.00 बजे, **नीलामी की अंतिम तिथि/समय :** दिनांक 06.03.2026, 12.30 बजे। ● **कैटेगरी : एमपीएस, नीलामी कैटलॉग सं. : सीएटीजी47, लॉट सं./कैटेगरी :** i) एमपीएस-एडीआरए-वीएसयू-एमपीएस-11-26-2 (एमपीएस-मल्टी परपज स्टॉल), **नीलामी शुरू (सभी लॉट):** दिनांक 06.03.2026, 12.00 बजे, **नीलामी की अंतिम तिथि/समय :** दिनांक 06.03.2026, 12.30 बजे। ● **कैटेगरी : कैटरिंग, नीलामी कैटलॉग सं. : सीएटीजी48, लॉट सं./कैटेगरी :** i) सीएटीजी-एडीआरए-बीयूआरएन-एसएमयू-86-26-2 (कैटरिंग-स्पेशल माइनर यूनिट (एसएमयू)), **नीलामी शुरू (सभी लॉट) :** दिनांक 09.03.2026, 12.00 बजे, **नीलामी की अंतिम तिथि/समय :** दिनांक 09.03.2026, 12.30 बजे। **टिप्पणी:** प्रत्याशित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे आईआरईपीएस वेबसाइट (**www.ireps.gov.in**) पर ई-नीलामी मॉड्यूल देखें। किसी भी पूछताछ/स्पष्टीकरण के लिए, कृपया अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से संपर्क करें।

(PR-1209) **वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, आद्रा**

दक्षिण पूर्व रेलवे
मुस्कान के साथ सेवा

पटना-हावड़ा-पटना स्पेशल ट्रेन

होली उत्सव के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए, 02024/02023 **पटना-हावड़ा-पटना स्पेशल** ट्रेन निम्नलिखित संक्षिप्त समयसूची, ठहराव, आवागमन की तिथियों और गठन के अनुसार चलेगी: -

पटना-हावड़ा			(02024) (02023)	हावड़ा-पटना		
दिन	आ.	प्र.	स्टेशन	आ.	प्र.	दिन
रविवार	--	**05.30**	↓ पटना	**22.30**	--	रविवार
	06.45	06.47	मोकामा जंक्शन	20.52	20.54	
	08.59	09.02	जसीडीह जंक्शन	18.26	18.29	
	10.43	10.47	आसनसोल	16.40	16.44	
	13.25	--	हावड़ा ↑	--	**14.15**	

उपर्युक्त स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में मार्ग में पटना साहिब, बख्तियारपुर जंक्शन, बाढ़, हाथीदा जंक्शन, लक्खीसराय जंक्शन, जमुई, झाझा, मधुपुर जंक्शन, जामताड़ा, चित्तरंजन और दुर्गापुर स्टेशनों पर भी रुकेंगी। ● **आवागमन के दिन/तिथि : पटना से 02024 और हावड़ा से 02023** दिनांक 08.03, 15.03, 22.03 और 29.03.2026 (रविवार) को = 4 ट्रिप। ● **गठन: दिनांक** 08.03, 15.03 **और** 22.03.2026 **के लिए :** एसी चेयर कार - 03, चेयर कार - 13, पावर कार - 01, एलएसएलआरडी - 01 = 18 कोच। **दिनांक 29.03.2026 के लिए:** एसी चेयर कार - 03, चेयर कार - 17, पावर कार - 01, एलएसएलआरडी - 01 = 22 कोच। ● **कैटेगरी:** मेल/एक्सप्रेस (सुपर फास्ट)।

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक

पूर्व रेलवे

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

सियालदह मंडल के तहत पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक के लिए ट्रेनों की नियंत्रण व्यवस्था

सियालदह मंडल के पार्क सर्कस स्टेशन में पुराने फूट ओवर ब्रिज को तोड़ने के लिए, **दिनांक 21.02.2026 (शनिवार) को रात 10.40 बजे से दिनांक 22.02.2026 (रविवार) को सुबह 06.40 बजे तक 08 घंटे के लिए पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक** आवश्यक होगा। फलस्वरूप, नीचे उल्लेखित ट्रेनें निम्नानुसार नियंत्रित की जाएंगी:

ट्रेनों का निरस्तीकरण

● **दिनांक 21.02.2026 (शनिवार) को : सियालदह-लक्ष्मीकांतपुर लोकल** - 34754 डाउन/34757 अप। **सियालदह-कैनिंग लोकल** - 34552 डाउन/34557 अप। **सियालदह-डॉयमण्ड हार्बर लोकल** - 34858 डाउन/34855 अप। **सियालदह-कोमागता मारु बजबज लोकल** - 34164 डाउन/34163 अप। ● **दिनांक 22.02.2026 (रविवार) को : सियालदह-सोनारपुर लोकल** - 34412 डाउन/34411 अप, **सियालदह-बारुईपुर लोकल** - 34612 डाउन, 34614 डाउन/34611 अप, 34613 अप, **सियालदह-कोमागता मारु बजबज लोकल** - 34114 डाउन, 34118 डाउन/34113 अप, **सियालदह-लक्ष्मीकांतपुर लोकल** - 34718 डाउन, **सियालदह-डॉयमण्ड हार्बर लोकल** - 34818 डाउन/34815 अप, **सियालदह-कैनिंग लोकल** - 34511 अप, **कोमागता मारु बजबज-नैहाटी लोकल** - 31051 अप, **नैहाटी-सियालदह लोकल** - 31422 डाउन।

ट्रेनों की संक्षिप्त यात्रा समाप्त/संक्षिप्त यात्रा शुरू

(1) **दिनांक 21.02.2026 (शनिवार)** को **34161 अप कोमागाता मारु बजबज-सियालदह लोकल** ट्रेन बालीगंज में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी तथा **दिनांक 22.02.2026 (रविवार)** को **34112 डाउन सियालदह-कोमागाता मारु बजबज लोकल** ट्रेन बालीगंज से संक्षिप्त यात्रा शुरु करेगी। (2) **दिनांक 21.02.2026 (शनिवार)** को **34857 अप डॉयमण्ड हार्बर-सियालदह लोकल** ट्रेन बालीगंज में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी तथा **34554 डाउन सियालदह-कैनिंग लोकल** ट्रेन बालीगंज से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी। (3) **दिनांक 21.02.2026 (शनिवार)** को **34859 अप डॉयमण्ड हार्बर-सियालदह लोकल** ट्रेन बालीगंज में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी तथा **दिनांक 22.02.2026 (रविवार)** को **34860 डाउन सियालदह-डॉयमण्ड हार्बर लोकल** ट्रेन (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 21.02.2026) बालीगंज से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी। (4) **दिनांक 21.02.2026 (शनिवार)** को **34436 अप सियालदह-सोनारपुर लोकल** ट्रेन बालीगंज में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी तथा **दिनांक 22.02.2026 (रविवार)** को **34812 डाउन सियालदह-डॉयमण्ड हार्बर लोकल** ट्रेन बालीगंज से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी। (5) **दिनांक 21.02.2026 (शनिवार)** को **34755 अप लक्ष्मीकांतपुर-सियालदह लोकल** ट्रेन सोनारपुर में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी। (6) **दिनांक 22.02.2026 (रविवार)** को **34711 अप लक्ष्मीकांतपुर-सियालदह लोकल** ट्रेन सोनारपुर में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी तथा **34712 डाउन सियालदह-लक्ष्मीकांतपुर लोकल** ट्रेन सोनारपुर से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी। (7) **दिनांक 22.02.2026 (रविवार)** को **34713 अप लक्ष्मीकांतपुर-सियालदह लोकल** ट्रेन सोनारपुर में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी तथा **34714 डाउन सियालदह-लक्ष्मीकांतपुर लोकल** ट्रेन सोनारपुर से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी। (8) **दिनांक 22.02.2026 (रविवार)** को **34715 अप लक्ष्मीकांतपुर-सियालदह लोकल** ट्रेन सोनारपुर में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी तथा **34716 डाउन सियालदह-लक्ष्मीकांतपुर लोकल** ट्रेन सोनारपुर से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी। (9) **दिनांक 22.02.2026 (रविवार)** को **34811 अप डॉयमण्ड हार्बर-सियालदह लोकल** ट्रेन बालीगंज में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी तथा **34814 डाउन सियालदह-डॉयमण्ड हार्बर लोकल** ट्रेन बालीगंज से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी। (10) **दिनांक 22.02.2026 (रविवार)** को **34813 अप डॉयमण्ड हार्बर-सियालदह लोकल** ट्रेन बालीगंज में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी तथा **34816 डाउन सियालदह-डॉयमण्ड हार्बर लोकल** ट्रेन बालीगंज से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी। (11) **दिनांक 22.02.2026 (रविवार)** को **34513 अप कैनिंग-सियालदह लोकल** ट्रेन सोनारपुर में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी तथा **34512 डाउन सियालदह-कैनिंग लोकल** ट्रेन सोनारपुर से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी। (12) **दिनांक 22.02.2026 (रविवार)** को **34111 अप कोमागाता मारु बजबज-सियालदह लोकल** ट्रेन बालीगंज में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी तथा **34116 डाउन सियालदह-कोमागाता मारु बजबज लोकल** ट्रेन बालीगंज से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी। (13) **दिनांक 22.02.2026 (रविवार)** को **34517 अप कैनिंग-सियालदह लोकल** ट्रेन सोनारपुर में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी तथा **34514 डाउन सियालदह-कैनिंग लोकल** ट्रेन सोनारपुर से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी। (14) **दिनांक 22.02.2026 (रविवार)** को **34791 अप नामखाना-सियालदह लोकल** ट्रेन बालीगंज में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी तथा **34720 डाउन सियालदह-नामखाना लोकल** ट्रेन बालीगंज से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी। ब्लॉक की अवधि के दौरान ट्रेनें विलम्ब से चल सकती है। असुविधा के लिए खेद है।

मंडल रेल प्रबंधक, सियालदह

पूर्व रेलवे

हमें अनुसरण करें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

धर्मतला का शताब्दी पुराना 'एल-20 बस स्टैंड' स्थानांतरित

कोलकाता, समाज्ञा : मेट्रो निर्माण कार्य के कारण धर्मतला स्थित शताब्दी पुराने 'एल-20 बस स्टैंड' को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब यात्री पुराने स्थान से बस नहीं पकड़ सकेंगे। उन्हें इसके लिए सामने स्थित 'धर्मतला सरकारी बस स्टैंड' जाना होगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, ईस्ट-वेस्ट मेट्रो के एसप्लानेड स्टेशन के पास नया बस स्टैंड तैयार किया गया है। अगले कुछ दिनों में दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम (एसबीएसटीसी) और उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम (एनबीएसटीसी) की करीब 200 बसें इसी नए स्टैंड से संचालित होंगी। जोका-एसप्लानेड मेट्रो कॉरिडोर के अंतर्गत एसप्लानेड स्टेशन के निर्माण के लिए यह कदम

उठाया गया है। जानकारी के मुताबिक, करीब 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र में नया स्टैंड बनाया जा रहा है। विधान मार्केट और एल-20 बस स्टैंड के इलाके में मेट्रो का काम तेज़ी से चलेगा, इसलिए इन स्थानों को हटाया जा रहा है। इस क्षेत्र में न्यू गड़िया-दक्षिणेश्वर, हावड़ा मैदान-सेक्टर फाइव और जोका-एसप्लानेड-तीनों मेट्रो लाइनों का संगम होगा। यहां तीन मंजिला स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे यात्री एक मेट्रो से उतरकर दूसरी मेट्रो में आसानी से जा सकेंगे। इसी बड़े ढांचे के निर्माण को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड को स्थानांतरित किया गया है। हालांकि, इस इलाके से चलने वाली निजी बसों को कब स्थानांतरित किया जाएगा, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही विधान मार्केट को भी हटाया जाएगा। रानी रासमणि एवेन्यू और सिधु कान्हू डहर के बीच नए स्थान पर दो मंजिला भवन में मार्केट का निर्माण होगा, जहां दुकानें, फूड कोर्ट, पार्किंग और शौचालय की सुविधा उपलब्ध होगी। नए बस स्टैंड के निर्माण का पूरा खर्च मेट्रो प्राधिकरण द्वारा वहन किया जा रहा है।

टेट : प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों की याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने उठाया देरी पर सवाल

कोलकाता, समाज्ञा : 22 फरवरी को होने वाली स्पेशल एजुकेटर टीईटी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगते हुए कुछ प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अदालत ने आवेदन की समयसीमा समाप्त होने के बाद याचिका दायर करने पर सवाल उठाते हुए इसे खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने पूछा कि जब आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर थी, तो उसके बाद अदालत में याचिका क्यों दायर की गई। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जिन अभ्यर्थियों को पहले परीक्षा में बैठने का अवसर मिला,

उन्होंने समय रहते अदालत का रुख किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने दलील दी कि यह बोर्ड की त्रुटि है। उनके अनुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों के तहत प्रशिक्षित और प्रशिक्षणरत दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यह परीक्षा पहली बार आयोजित हो रही है और पात्रता को लेकर पूर्व में स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए थे, जिनका पालन नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2026 की इस परीक्षा में प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, जिसके विरोध में यह याचिका दायर की गई थी। हालांकि अदालत ने देरी को आधार बनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

रॉयल स्टैग बूमबॉक्स ने कोलकाता में मचाया धमाल

कोलकाता : रॉयल स्टैग बूमबॉक्स - द ओरिजिनल साउंड ऑफ जेनरेशन लार्ज - अब कोलकाता में पहुंच रहा है, जहां बॉलीवुड की सदाबहार धुनों का संगम हिप-हॉप की जोशीली ऊर्जा के साथ देखने को मिलेगा। मंच से आगे बढ़कर यह फेस्टिवल एक इमर्सिव स्पेस में बदल जाता है, जहां गेमिंग और समकालीन पॉप कल्चर लाइव एंटरटेनमेंट को एक नई परिभाषा देते हैं। इसमें अरमान मलिक, डिनो जेम्स, फॉसिल्स, डीजे साहिल गुलाटी और पायल धरे की शानदार प्रस्तुतियां होंगी। तारीख - 21 फरवरी 2026, स्थान - एक्काटिका ग्राउंड, समय - दोपहर 3 बजे से आगे। टिकट स्किल बॉक्स पर उपलब्ध है।

एसआईआर : मालदह में स्क्रूटिनी के आतंक से बीएलओ की मौत

मालदह : राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में आ गई है। चुनावी ड्यूटी के दौरान एक और बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की मौत ने इस प्रक्रिया और उससे जुड़े दबावों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक की पहचान मोहम्मद अनिकुल आलम (54) के रूप में की गई है। वह मालदह जिले के कालियाचक हाई स्कूल में असिस्टेंट टीचर थे और सुजापुर के निवासी थे। उन्हें सुजापुर क्षेत्र के बूथ नंबर 144 का बीएलओ नियुक्त किया गया था। पीड़ित परिवार के मुताबिक, बुधवार को 44 लोगों के एसआईआर फॉर्म वापस आए थे, जिनमें उनका अपना फॉर्म भी शामिल था। परिजनों ने दावा किया कि बुधवार की सुबह उन्हें

सीने में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उन्होंने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बावजूद, वे चुनावी काम से जुड़े जरूरी काम के लिए बीडीओ ऑफिस चले गए। वहां से लौटते समय उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक मोहम्मद अनिकुल आलम के बेटे ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए।

मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन का 9 कर्मचारियों के निलंबन के खिलाफ 22वें दिन भी धरना जारी

कोलकाता, समाज्ञा : मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से 9 कर्मचारियों के निलंबन के विरोध में अस्पताल परिसर के बाहर जारी धरना 22वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारी संगठन प्रबंधन के निर्णय को गलत बताते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध सभा में अस्पताल मैनेजमेंट के द्वारा कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में राज गृह सिंह, डॉ ए.के सिंह, डॉ लाला, बद्री नारायण मिश्रा, राकेश राय, विकास यादव, अजय उपाध्याय, कमर ईह्लाही, अजित सिंह, बाबू नंद पाण्डेय, मुकेश दास, राजेश सिंह,प्रेम कुमार सिंह, गोविंद पांडेय, रवि शर्मा, विनोद ओझा, उदय यादव, नरेन्द्र शर्मा, रिषभ पांडेय, तिरलोकी नाथ, संजीत सिंह,अजित साह, मुनेश पांडेय, गोविंद सिंह, नंदू सोनकर, रणविजय सिंह, सत्येन्द्र सिंह,गोपाल सिंह, राजेश

सिंह,अरूण सिंह, प्रदीप मिश्र ने अपने विचार व्यक्त किए।

इस दौरान बिजेंद्र प्रसाद सिंह, सरोज मिश्रा, अशोक गुप्ता, मंहगू सिंह, शंकर चौधरी, मुकुंद पाण्डेय, सुरेश सिंह, श्रीराम शर्मा, सुशांत कानारार, हेमंत शर्मा, अमर चौधरी, बबलू सिंह उपस्थित रहे। इस बीच प्रबंधन की ओर से कहा गया हैं कि कुछ शर्तो के आधार पर ही निष्कासित किए गए कर्मचारियों को ज्वाइन करवाया जायेगा। हालांकि श्रमिक संगठन ने इन शर्तों को अस्वीकार्य बताते हुए स्पष्ट किया है कि वे इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे।

कार्यक्रम में सभा की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष श्रमिक नेता संतोष सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि संगठन श्रम कानूनों के तहत जो भी न्यायसंगत होगा, उसी को स्वीकार करेगा और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

भारत टैक्सी और जीएसटी पर बहस तेज, ड्राइवर हितों के लिए नीति स्पष्टता की मांग

कोलकाता, समाज्ञा : ड्राइवर-स्वामित्व और सब्सक्रिप्शन आधारित राइड प्लेटफॉर्म 'भारत टैक्सी' के विस्तार के साथ जीएसटी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। गिग इकोनॉमी में उभरता यह मॉडल पारंपरिक कमीशन आधारित एग्रीगेटर्स के विपरीत काम करता है, जहां ड्राइवर टेक्नोलॉजी एक्सेस के लिए सदस्यता शुल्क देते हैं और किराया सीधे यात्री से तय करते हैं। प्लेटफॉर्म न तो किराया नियंत्रित करता है और न ही भुगतान संभालता है। ऐसे में प्रस्तावित 5 प्रतिशत जीएसटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसे ई-कॉमर्स एग्रीगेटर की तरह टैक्स दायरे में लाया जा सकता है।

जीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत टैक्स देयता तभी

बनती है जब प्लेटफॉर्म सप्लाई और भुगतान नियंत्रित करे। ड्राइवर संगठनों का कहना है कि अधिकांश ड्राइवर 20 लाख रुपये वार्षिक आय की सीमा से काफी नीचे हैं और जीएसटी से बाहर हैं। तमिलनाडु ऑटो कॉल टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन फेडरेशन ने सरकार से एसएएएस और कमीशन मॉडल में स्पष्ट अंतर करने की मांग की है। उनका तर्क है कि हर राइड पर जीएसटी से ड्राइवरों की आय घटेगी।

भाजपा से चुनाव लड़ेंगी रिंकू मजूमदार? बायोडाटा जमा करने पर दिलीप घोष ने दी प्रतिक्रिया

कोलकाता : भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में रिंकू मजूमदार द्वारा प्रत्याशी बनने के लिए बायोडाटा जमा किए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, उनकी इच्छा हुई, इसलिए आवेदन किया है।

गुरुवार को ईको पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान मीडिया से बातचीत में दिलीप घोष ने कहा, वह मुझसे भी पुरानी कार्यकर्ता हैं। लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रही हैं। मैं विधायक और सांसद बन गया,

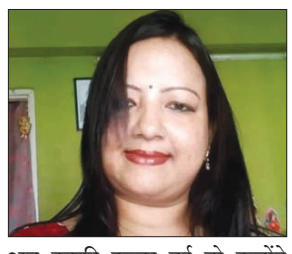

अब उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने आवेदन किया। हजारों लोगों ने आवेदन किया है। उम्मीदवार कौन होगा, यह पार्टी तय करेगी।

सूत्रों के मुताबिक, 31 जनवरी को रिंकू मजूमदार ने सॉल्टलेक स्थित भाजपा कार्यालय में अपना जीवनवृत्त जमा किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने तीन सीटों-मेदिनीपुर शहर, बीजपुर और न्यूटाउन-से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है।

जमा किए गए बायोडाटा में उन्होंने खुद को जमीनी स्तर और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता बताया है। साथ ही पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों में अपनी भूमिका का उल्लेख भी किया है।

हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा।

हावड़ा-पटना और जमालपुर-सहरसा के बीच चलेगी होली स्पेशल ट्रेन

कोलकाता, समाज्ञा : पूर्व रेलवे होली के त्योहार के दौरान विशेष ट्रेनों का संचालन कर रही है। इसके तहत हावड़ा एवं पटना के बीच चार-चार फेरे के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। जानकारी के अनुसार, 02024 पटना-हावड़ा स्पेशल ट्रेन प्रत्येक रविवार को 8 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026 के बीच पटना से प्रातः 05:30 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 13:25 बजे हावड़ा पहुंचेगी। इसी प्रकार, 02023 हावड़ा-पटना स्पेशल ट्रेन प्रत्येक रविवार को 8 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026 के बीच हावड़ा से 14:15 बजे रवाना होगी और उसी दिन 22:30 बजे पटना पहुंचेगी। यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, जामताड़ा, मधुपुर एवं जसीडीह स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन में नॉन-एसी सीटिंग एवं एसी चेयर कार की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

इसके अतिरिक्त, रेलवे ने जमालपुर और सहरसा के बीच चलने वाली मेमू विशेष ट्रेन सेवा को भी जारी रखने का निर्णय लिया है। 05509/05510 सहरसा-जमालपुर-सहरसा मेमू स्पेशल ट्रेन अपने वर्तमान मार्ग, ठहराव एवं समयानुसार 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रतिदिन दोनों दिशाओं में संचालित होगी।

आरवीएनएल के सीएमडी सलीम अहमद ने कोलकाता में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की

कोलकाता, समाज्ञा : रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), नई दिल्ली के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सलीम अहमद ने 18 फरवरी को आरवीएनएल की कोलकाता इकाई का दौरा कर यहां संचालित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान श्री अहमद ने भूमिगत टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से चल रहे सुरंग निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वर्तमान में दो टीबीएम टीबीएम दुर्गा और टीबीएम दिव्या की सहायता से टनल बोरिंग कार्य किया जा रहा है। दोनों मशीनों ने सेंट थॉमस लॉन्चिंग शाफ्ट से खुदाई शुरू की है और विक्टोरिया स्टेशन की ओर अग्रसर हैं। टीबीएम दुर्गा लगभग 1100 मीटर तथा टीबीएम

दिव्या लगभग 650 मीटर सुरंग निर्माण कार्य पूरा कर चुकी है। सीएमडी ने कार्य में सुरक्षा और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने नव-निर्मित बी.सी. रॉय मार्केट का भी निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बेलियाघाटा से आईटी सेंटर तक ऑरेंज लाइन मेट्रो परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। दौरे के दौरान श्री अहमद ने मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक एस.एस मिश्रा से मुलाकात कर परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इस समीक्षा बैठक में आरवीएनएल, कोलकाता के अधिकारी भी उपस्थित थे।

120 अमेरिकी सीईओ भारत की एआई क्षमता को गति देने के लिए दिल्ली पहुंचे

कोलकाता : एडोब के चेयरमैन शांतनु नारायण, फ़ेडेक्स के प्रेसिडेंट ठरक्ष राज सुब्रमण्यम, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ और जनरल कैटालिस्ट के सीईओ हेमंत तनेजा सहित 120 अमेरिकी सीईओ का प्रतिनिधिमंडल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचा। अमेरिकी टेक कंपनियां अगले पांच वर्षों में भारत में एआई और डेटा सेंटर अवसंरचना में 67.5 अरब डॉलर के निवेश की तैयारी कर रही हैं। गुंटूर ने साझा किया कि एचसीएल टेक आधे कार्यबल के साथ राजस्व दोगुना करने का लक्ष्य रख रहा है, साथ ही 4,000 नई भूमिकाएं तैयार कर रहा है जो 18 महीने पहले मौजूद नहीं थीं। राघवन ने कहा कि जीई हेल्थकेयर के पास एफडीए से स्वीकृत एआई समाधानों की सबसे बड़ी संख्या है। हरजीव सिंह ने कहा, भारत के पास प्रतिभा और महत्वाकांक्षा दोनों हैं।

केशपुर में लॉरी-स्कूटी टक्कर, एक की मौत व एक घायल

पश्चिम मेदिनीपुर : जिले के केशपुर इलाके में गुरुवार को सड़क दुर्घटना में लॉरी और स्कूटी की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक का नाम शेख सौरव है। मृतक केशपुर के 11 नंबर क्षेत्र का निवासी बताया गया है। पुलिस के अनुसार, केशपुर से मेदिनीपुर की ओर जा रही एक लॉरी ने 12 माइल इलाके में अचानक नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रही स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद लॉरी सड़क किनारे स्थित एक घर में जा घुसी, जिससे मकान को भारी नुकसान पहुंचा और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में स्कूटी चालक शेख सौरव की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से निकालकर मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस घर में ट्रक घुसी, वहां किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि मकान का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर केशपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। दुर्घटनाग्रस्त लॉरी अभी भी घर के अंदर फंसी हुई है।

सियालदह स्टेशन पर स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक 'ग्लोरियस कोलकाता रिटर्न डे' मनाया गया

कोलकाता, समाज्ञा : स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक कोलकाता आगमन की स्मृति में बुधवार को सियालदह स्टेशन पर 'ग्लोरियस कोलकाता रिटर्न डे' श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। यह दिवस 19 फरवरी 1897 को उनके विजयी पश्चिमी देशों के दौरे के बाद कोलकाता लौटने की गौरवपूर्ण घटना की याद दिलाता है।

इस ऐतिहासिक अवसर की 129वीं वर्षगांठ पर पूर्व रेलवे द्वारा बजबज से सियालदह तक एक विशेष ट्रेन चलाई गई। 19 फरवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा से लौटकर पहले बजबज स्टेशन पहुंचे थे। उसी ऐतिहासिक यात्रा की पुनरावृत्ति करते हुए विशेष ट्रेन को फूलों और प्रेरणादायक उद्धरणों से सजाया गया। बजबज से कोलकाता तक स्वामी जी की एक प्रतिमा भी लाई गई, जिससे उनकी ऐतिहासिक वापसी को प्रतीकात्मक रूप से दोहराया गया।

सियालदह स्टेशन पर इस विशेष ट्रेन का स्वागत रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, गोलपार्क के सन्यासियों ने किया। इस अवसर पर सियालदह मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजीव सक्सेना सहित कई वरिष्ठ रेल अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह विशेष ट्रेन यात्रा स्वामी विवेकानंद के भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना पर पड़े गहरे प्रभाव को श्रद्धांजलि देने का माध्यम बनी। उनके विचार और आदर्श आज भी देश-विदेश में करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य उनके संदेश की मूल भावना को पुनर्जीवित करना और एक एकजुट एवं प्रगतिशील भारत के उनके स्वप्न को सशक्त करना था। 'ग्लोरियस कोलकाता रिटर्न डे' प्रतिवर्ष उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, ताकि स्वामी विवेकानंद की अमूल्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित किया जा सके।

पश्चिम मेदिनीपुर में दंपति का लटकता शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी

पश्चिम मेदिनीपुर : मेदिनीपुर शहर के पास गोपगढ़ हेरिटेज एंड इको-पार्क के पास बुधवार की रात एक दुखद घटना घटी। स्थानीय लोगों ने देखा कि एक पेड़ से एक दंपति का शव लटका हुआ है। सूचना मिलने पर मेदिनीपुर कोतवाली थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शवों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। मृतकों की पहचान पिंटू दास (38) और उनकी पत्नी मधुमिता दास (32) के रूप में हुई है। दोनों मेदिनीपुर के बानपड़ा इलाके के निवासी थे। शुरुआती जांच के आधार पर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक पिंटू दास मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत थे और साथ ही सेल्समैन का काम भी करते थे। उनके भाई कृष्ण दास ने बताया कि पिंटू और उनकी पत्नी के बीच

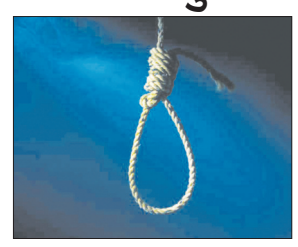

कोई विवाद नहीं था और वे यह समझ नहीं पा रहे कि दंपति ने आत्महत्या क्यों की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिंटू दास पिछले कुछ समय से अत्यधिक कर्ज और लेनदारों के बार-बार दबाव में तनाव में थे। अपमान और मानसिक पीड़ा सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया हो सकता है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल का निरीक्षण जारी है। आत्महत्या के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है।

पूर्व रेलवे के दौरे पर आरपीएफ महानिदेशक, सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा

कोलकाता, समाज्ञा : पूर्व रेलवे के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचीं आरपीएफ की महानिदेशक सोनाली मिश्रा ने 18-19 फरवरी को सुरक्षा प्रबंधन, निगरानी तंत्र और परिचालन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। फेयरली प्लेस स्थित पूर्व रेलवे मुख्यालय में आयोजित 'सुरक्षा सम्मेलन' की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, अपराध नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने तथा फील्ड इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद, उन्होंने पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद के. देउस्कर के साथ बैठक कर विभिन्न सुरक्षा एवं प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। महानिदेशक ने पश्चिम बंगाल के

पुलिस महानिदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। बैठक में आरपीएफ और राज्य पुलिस के बीच समन्वय को और प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। उन्होंने सुरक्षा निगरानी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित प्रणालियों को शामिल करने और सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम को उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दौरे के दौरान उन्होंने कालीघाट मेट्रो स्टेशन और एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजाम, भीड़ प्रबंधन और आरपीएफ की तैनाती का जायजा लिया। उन्होंने पूर्व रेलवे और मेट्रो रेलवे कोलकाता में आरपीएफ के कार्यों की सराहना करते हुए सुरक्षित और यात्री-अनुकूल रेलवे वातावरण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

हावड़ा मंडल में पुल विकास कार्य के कारण ईएमयू लोकल ट्रेनें रद्द

कोलकाता, समाज्ञा : पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन अंतर्गत तारकेश्वर शाखा खंड में पुल संख्या 11 पर आर्च ब्रिज को आरसीसी बॉक्स से प्रतिस्थापित करने के लिए 21 फरवरी की रात 23:20 बजे से 22 फरवरी की सुबह 09:20 बजे तक (कुल 10 घंटे) पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। यह कार्य शेवड़ाफुली और दियारा स्टेशनों के बीच दियारा स्टेशन सीमा के डाउन एवं कॉमन लूप लाइन पर किया जाएगा। इस कारण, 21 फरवरी 2026 (शनिवार) को डाउन दिशा में गोघाटा-हावड़ा (37384) और तारकेश्वर-हावड़ा (37358) ईएमयू लोकल ट्रेनें तथा अप दिशा में हावड़ा-गोघाटा (37389) और हावड़ा-तारकेश्वर (37351) ईएमयू लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी।

इसी प्रकार, 22 फरवरी 2026 (रविवार) को डाउन दिशा में तारकेश्वर-हावड़ा की ट्रेनें संख्या 37312, 37314, 37316, 37318, 37320, 37322, 37324 एवं 37326, तारकेश्वर-शेवड़ाफुली (37414, 37416), गोघाट-हावड़ा (37372, 37374) तथा हरिपाल-हावड़ा (37302) रद्द रहेंगी। वहीं, अप दिशा में हावड़ा-तारकेश्वर की ट्रेनें संख्या 37311, 37313, 37315, 37317, 37319, 37321 एवं 37323, शेओराफुली-तारकेश्वर (37413, 37415), हावड़ा-गोघाट (37371, 37373, 37375) तथा हावड़ा-हरिपाल (37301) ईएमयू लोकल ट्रेनें निरस्त रहेंगी।

अमृत भारत योजना से ऐतिहासिक मालदह टाउन स्टेशन को मिलेगा आधुनिक और भव्य स्वरूप

कोलकाता, समाज्ञा : उत्तर बंगाल के ऐतिहासिक शहर मालदह का प्रमुख रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से लैस नए स्वरूप में नजर आएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मालदह टाउन स्टेशन का व्यापक आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिस पर लगभग 35 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है।

महानंदा और कालिंदी नदियों की उपजाऊ धरती पर बसा मालदह अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित बड़ा सोना मस्जिद, फिरोज मीनार तथा पंडुआ की अदीना मस्जिद जैसे ऐतिहासिक स्थल इस क्षेत्र को विशेष पहचान देते हैं। वर्षों से यह स्टेशन पर्यटकों के लिए नवाबी इतिहास का प्रवेशद्वार रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन भवन के बाहरी हिस्से को आकर्षक और आधुनिक डिजाइन में विकसित किया जा रहा है। विस्तृत सर्कुलेटिंग एरिया, उन्नत कॉनकोर्स, एयर-कूलिंग और एएजॉस्ट सिस्टम जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। प्लेटफार्मों का उन्नयन कर उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाएगा। यात्रियों के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, लाउंज,

फूड कोर्ट और पर्याप्त पेयजल व्यवस्था की जाएगी।

इसके अलावा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और सूचना कियोस्क लगाए जा रहे हैं। बहु-स्तरीय पार्किंग, नई लिफ्ट और एस्केलेटर स्टेशन को अत्याधुनिक स्वरूप देंगे। अधिकारियों का मानना है कि इस आधुनिकीकरण से न केवल यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मालदह के प्रसिद्ध फजली आम और रेशम उद्योग को भी बेहतर परिवहन व्यवस्था का लाभ मिलेगा। परियोजना के पूर्ण होने के बाद मालदह टाउन स्टेशन उत्तर बंगाल के विकास का नया केंद्र बनकर उभरेगा।

बेलडांगा मामले में नया कानूनी विवाद, एनआईए को जानकारी देने पर राज्य की आपत्ति

❑ **तीसरी बार भी आरोपितों की नहीं हो सकी कोर्ट में पेशी, एनआईए बोली... 'खुद लाएंगे आरोपित'**

कोलकाता : बेलडांगा मामले को लेकर एक बार फिर कानूनी जंग तेज हो गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। राज्य का कहना है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को मामले से जुड़ी जानकारी सौंपने पर उसे आपत्ति है।

राज्य सरकार ने सवाल उठाया है कि जब मामला पहले से ही हाई कोर्ट में विचाराधीन है, तब निचली

अदालत किस आधार पर सूचना हस्तांतरण का निर्देश दे सकती है। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है।

इसी मामले में दूसरी ओर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भी गुरुवार को अदालत पहुंची। एजेंसी का आरोप है कि बेलडांगा मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोलकाता की अदालत में पेश करने में बार-बार बाधा आ रही है। राज्य पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण आरोपियों को लाना संभव नहीं हो पा रहा।

एनआईए ने अदालत को बताया कि इससे पहले दो बार आरोपियों को कोलकाता नहीं लाया जा सका और पिछली सुनवाई में उन्हें वर्चुअल माध्यम से पेश किया गया था। एजेंसी का तर्क है कि जांच के हित में आरोपियों की भौतिक उपस्थिति जरूरी है। इसलिए उसने अदालत से अनुमति मांगी है कि वह स्वयं सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर आरोपियों को कोलकाता ला सके।

12 फरवरी को मुर्शिदाबाद जिला पुलिस की ओर से 'रेडियोग्राम' के माध्यम से सूचित किया गया था कि उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के कारण पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, इसलिए एस्कॉर्ट देना संभव नहीं है। हालांकि एनआईए का दावा है कि कई अनुरोधों के बावजूद सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई।

राज्य और केंद्रीय एजेंसी के बीच इस टकराव के चलते मामले की प्रगति पर अनिश्चितता बनी हुई है। एक ओर सूचना हस्तांतरण को लेकर कानूनी सवाल हैं, तो दूसरी ओर आरोपियों की पेशी को लेकर प्रशासनिक जटिलता-इन सबके बीच बेलडांगा मामला फिर से राजनीतिक और कानूनी रूप से अहम बन गया है।

बेलडांगा हिंसा : एनआईए ने मुर्शिदाबाद पुलिस से मांगी केस डायरी

कोलकाता, समाज्ञा : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने गुरुवार को मुर्शिदाबाद जिले की पुलिस को ईमेल भेजकर पिछले महीने बेलडांगा में हुई हिंसा से संबंधित केस डायरी उपलब्ध कराने को कहा है। एनआईए के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक बेलडांगा हिंसा मामले की केस डायरी एनआईए को सौंपे जाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बेलडांगा हिंसा मामले की केस डायरी 26 फरवरी तक प्रस्तुत की जाए। फिलहाल, एनआईए इस मामले में मुर्शिदाबाद पुलिस की अगली कार्रवाई पर नजर रखे हुए है।

बच्चा चोरी की अफवाह पर मां-बेटी को जलाकर मारने की कोशिश

25 आरोपित दोषी करार

आज चुंचुड़ा अदालत का फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगा सजा का ऐलान

हुगली, समाज्ञा : चुंचुड़ा अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश पीयूष कांति राय ने बच्चा चोरी की अफवाह में मां-बेटी को जलाकर मारने की कोशिश करने के मामले में सभी 25 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता शंकर गांगुली ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि उस समय बच्चा चोरी की अफवाहों के कारण कई घटनाएं हुई थीं और आसनपुर की यह घटना बेहद गंभीर थी, जिसमें एक सम्मानित परिवार की दो महिलाओं के साथ मारपीट की गई, चालक को पीटा गया, गाड़ी जला दी गई और पुलिस पर तीर से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि जिन धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है, उनमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। एक ही मामले में 25 लोगों को एक साथ दोषी ठहराया जाना दुर्लभ घटना है। सजा पर अंतिम फैसला आज सुनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बालागढ़ थाना क्षेत्र के आसनपुर गांव में वर्ष 2017 में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते मां-बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश और पुलिस पर हमले के मामले में चुंचुड़ा अदालत ने 25 आरोपियों को दोषी ठहराया है।

जानकारी के अनुसार, कल्याणी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की पत्नी रंजुबाला घोष अपनी बेटी अपर्णा घोष के साथ आसनपुर गांव में घरेलू सहायिका की तलाश में गई थीं। उनके साथ मारुति कार के चालक विश्वनाथ मंडल भी थे। 21 जनवरी 2017 की शाम गांव में अजनबी लोगों को देखकर बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई। उग्र ग्रामीणों ने उनकी कार को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। भीड़ ने मारुति कार में आग लगा दी। सूचना मिलने पर बालागढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस पर भी हमला किया गया। 11 पुलिसकर्मी और सिविक वॉलंटियर घायल हुए। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया। 20 अप्रैल 2021 को आरोप तय हुए। इस मामले में ग्रामीणों, चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों और पीड़ितों सहित कुल 27 गवाहों ने बयान दिया।

वाम मोर्चे में सीट बंटवारे पर बनी रही खींचतान

सहयोगियों से सहमति नहीं बना सके विमान-सलीम

कोलकाता : आगामी चुनाव को लेकर वाम मोर्चे में सीट समझौते पर जारी गतिरोध बुधवार को भी नहीं सुलझ सका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ओर से उम्मीद जताई गई थी कि बैठक में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का मसला अंतिम रूप ले लेगा, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। अलीमुद्दीन स्ट्रीट स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के साथ लंबी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, फॉरवर्ड ब्लॉक 23 से कम सीटों पर तैयार नहीं है, जबकि माकपा ने 18 से अधिक सीटें देने से इनकार किया है। आरएसपी ने 23 सीटों की मांग की थी, जिसे घटाकर 19 कर दिया गया है, लेकिन माकपा 15 से ज्यादा सीट देने को राजी नहीं है। सीपीआई ने 18 सीटों की मांग रखी है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि औपचारिक सहमति नहीं बन सकी, लेकिन चर्चा सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। सीट बंटवारे को लेकर जटिलता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि जिन कई सीटों पर सहयोगी दल दावा कर रहे हैं, उन पर माकपा और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) भी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं फॉरवर्ड ब्लॉक ने आईएसएफ के साथ गठबंधन पर आपत्ति जताई है। बताया गया है कि 20 तारीख को फॉरवर्ड ब्लॉक की राज्य समिति की बैठक है, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद माकपा सहयोगी दलों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का दौर फिर शुरू कर सकती है, जहां सीट समझौते पर अंतिम सहमति बनने की संभावना है।

मिमी चक्रवर्ती को मानहानि का नोटिस, इवेंट आयोजक ने मांगे 20 लाख रुपये

कोलकाता, समाज्ञा : कार्यक्रम आयोजक तनय शास्त्री ने अभिनेत्री और पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है। शास्त्री ने आरोप लगाया है कि उत्पीड़न के मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर उनकी छवि खराब की गई, जिसके लिए उन्होंने 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है। शास्त्री ने गुरुवार को बताया कि उनके वकील के माध्यम से मिमी चक्रवर्ती को कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि या तो वह माफी मांगें और 20 लाख रुपये का भुगतान करें, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। इस घटनाक्रम पर मिमी चक्रवर्ती की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तनय शास्त्री का दावा है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मिमी चक्रवर्ती को 2.65 लाख रुपये दिए गए थे। उनके अनुसार, अभिनेत्री निर्धारित समय पर कार्यक्रम में नहीं पहुंचीं, जिसके कारण उन्हें मंच छोड़ने के लिए कहा गया। शास्त्री ने यह भी आरोप लगाया कि बिना कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, जिसके चलते उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में मिमी चक्रवर्ती को प्रस्तुति देनी थी। वह उस रात की अंतिम कलाकार थीं। मिमी चक्रवर्ती का आरोप था कि आधी रात के बाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं होने के कारण तनय शास्त्री ने उन्हें प्रस्तुति के दौरान मंच से हटा दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके जवाब में, तनय शास्त्री ने जवाबी शिकायत करते हुए कहा था कि अभिनेत्री समय पर नहीं पहुंचीं और उनसे विनम्रतापूर्वक मंच छोड़ने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने किसी तरह के उत्पीड़न से इनकार किया था। हालांकि, मामले की जांच के दौरान पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में शास्त्री और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद तनय शास्त्री को एक सप्ताह से अधिक समय न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। बाद में, 11 फरवरी को उन्हें जमानत मिली। अब मानहानि का नोटिस भेजे जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच एक और कानूनी लड़ाई शुरू होने की संभावना है।

स्कूल में घुसकर शिक्षक को धमकाने के आरोप में भाजपा विधायक पर एफआईआर दर्ज

बांकुड़ा : स्कूल अधिकारियों ने इंदास के भाजपा विधायक निर्मल कुमार धारा के खिलाफ बिना इजाजत क्लासरूम में घुसने और एक शिक्षक से झगड़ा करने के आरोप में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि पिछले मंगलवार को भाजपा विधायक इंदास के कुशमुरी हाई स्कूल में घुस गए थे। वे बिना इजाजत क्लासरूम में घुस गए और एक शिक्षक से झगड़ा कर लिया। वे असल में 'दादागिरी' करते दिखे। इसके बाद, बुधवार को स्कूल मैनेजमेंट कमिटी ने इस मामले को लेकर एक आपात बैठक बुलाई थी। उस बैठक में थाने में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया गया। उसके बाद, बुधवार की रात स्कूल अधिकारियों ने भाजपा विधायक के खिलाफ इंदास थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, थाने में शिकायत दर्ज कराने की घटना ने एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को नई दिशा देता 'इलेक्ट्रा 2026' तीन दिवसीय भव्य ट्रेड फेयर

❑ आज होगा सीडा की वेबसाइट व मोबाइल ऐप लॉन्च
❑ 1600 से अधिक सदस्यों को मिलेगी डिजिटल सुविधा

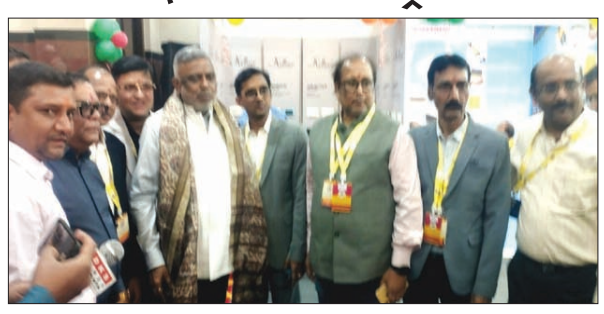

कोलकाता, समाज्ञा : कलकत्ता इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन (सीडा) की ओर से आठवां तीन दिवसीय इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड फेयर 'इलेक्ट्रा 2026' का गुरुवार को टी बोर्ड के निकट स्थित कच्छी जैन भवन में भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन मैथन एलॉय लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं सीएआइटी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल तथा केईआई इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह ने संयुक्त रूप से किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोलकाता नगर निगम के मेयर-इन-काउंसिल के सदस्य एवं तृणमूल विधायक देवाशीष कुमार ने कहा कि इस इलेक्ट्रिक गढ़ में इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े व्यापारियों के हित में यह संगठन बेहतरीन तरीके से कार्य करता आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी व्यापारियों के व्यवसाय में बढ़ोतरी को लेकर सदैव सहयोग करती आई हैं। इस व्यवसायिक गढ़ की और अधिक तेजी से प्रगति हो सके, इसे लेकर हमारा सहयोग हमेशा बना रहेगा। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक वर्मा ने बताया कि देश के सबसे बड़े विद्युत संगठनों में से एक के रूप में सीडा संगठित व्यापार विकास और आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। यह संगठन 1600 से अधिक सदस्यों की सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। इलेक्ट्रा 2026 उद्योग के आधुनिकीकरण और व्यवस्थित व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने का बड़ा अवसर है। 20 फरवरी को सीडा अपनी नवीनीकृत आधिकारिक वेबसाइट और पहला मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च करेगा, जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। यह ऐप सदस्यों के बीच डिजिटल संपर्क का माध्यम बनेगा तथा सदस्यता निर्देशिका, संचार और संचालन को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा।

इस मौके पर संस्था की इलेक्ट्रा 2026 ट्रेड फेयर कमेटी के चेयरमैन सत्य प्रकाश साव ने बताया कि इस वर्ष ट्रेड फेयर में 44 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें सोलर से जुड़े उपकरणों से लेकर अकाउंट्स से संबंधित विभिन्न प्रकार के अन्य इलेक्ट्रिकल सरंजाम तथा बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े स्टॉल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यहां छोटे से लेकर बड़े हर स्तर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक मंच पर लाया गया है, जिससे यहां आने वाले लोग काफी लाभान्वित हो सकें। इस अवसर पर सीडा के मीडिया सेल के संयोजक संजय कुमार सिंह ने बताया कि तीन दिनों तक चलने वाले इस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड फेयर में कमेटी के को-चेयरमैन हरि प्रपन थराद के साथ सीडा के उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंघी, सचिव गगन दीप मुंधड़ा, कोषाध्यक्ष तारक नाथ जायसवाल, मिनेश ठक्कर, अनिल कुमार सिंह, अरुण कोठारी, आनंद प्रकाश चांदगोठिया, बिपिन गोयल, चंद्रेश एस. मेघानी, मनोज सिंह, राजीव राठी, जितेंद्र सुराणा, कमल सुराणा, संजय कुमार सिंघी, बृजेश लड्ढा, आदित्य मोहनका, अविनाश वर्मा, नवल किशोर सिंह, आलोक कुमार सिंह, मुकेश सिन्हा और विकास राठी सहित बड़ी संख्या में सम्मानित लोग मौजूद थे।

उच्च माध्यमिक : गणित परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर सवालों का आरोप

कोलकाता, समाज्ञा : पिछले गुरुवार से 2026 की उच्च माध्यमिक परीक्षा का अंतिम सत्र शुरू हुआ है। इस वर्ष पहली बार सत्र आधारित प्रणाली के तहत परीक्षा ली जा रही है। अब तक परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही थी, लेकिन गुरुवार को गणित की परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर तीन प्रश्न आने के आरोप के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस मुद्दे को लेकर परीक्षार्थी और अभिभावक चिंतित हैं, वहीं शिक्षानुरागी संगठन भी मुखर हो उठे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि गणित प्रश्नपत्र में कुछ ऐसे सवाल थे, जिनके उत्तर निर्धारित समय के भीतर लिखना कठिन था। शिक्षकों का आरोप है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़ा एक प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर था। यह प्रश्न पांच (ए) में दिया गया था, जिसके पूरे दो अंक थे। इसके अलावा, प्रश्न 11(बी) और (सी) को भी पाठ्यक्रम से बाहर बताया जा रहा है, जिनमें चार-चार अंक निर्धारित थे। इस तरह कुल 10 अंकों के प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर होने का दावा किया जा रहा है। शिक्षकों का यह भी कहना है कि कुछ प्रश्न ऐसे थे, जिन्हें सीमित समय और निर्धारित उत्तरपुस्तिका में हल करना छात्रों के लिए व्यावहारिक रूप से कठिन था। शिक्षकों की शिकायत सामने आने के बाद पश्चिम बंग उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कहा गया है कि पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, परिषद के अध्यक्ष चिरंजीब भट्टाचार्य ने तीनों प्रश्न गलत होने के आरोप को खारिज किया है। उनका कहना है कि दो प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर के रूप में चिह्नित किया गया है और छात्रहित में परिषद जो भी जरूरी होगा, वह करेगी।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रचनात्मक वीडियो निर्माण प्रतियोगिता

हुगली, समाज्ञा : जिला पुलिस और आरामबाग महकमा पुलिस की पहल पर, आरामबाग नेताजी महाविद्यालय के सहयोग से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए रचनात्मक वीडियो निर्माण प्रतियोगिता का फाइनल चरण बुधवार को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 1 से 2 मिनट की अवधि वाले वीडियो का विषय था डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराध जागरूकता ग्रीन आरामबाग, स्वच्छ आरामबाग सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की नागरिकों द्वारा सहायता, महिला सुरक्षा में पुलिस की प्राथमिकता, तथा आरामबाग पुलिस का एक दिन विषय पर पुलिस की विभिन्न भूमिकाएं। प्रतियोगिता में किसी भी व्यक्ति, धर्म, राजनीतिक दल, जाति या समाज के संबंध में टिप्पणी करना पूरी तरह प्रतिबंधित था। प्रतिभागियों द्वारा भेजे गए सर्वश्रेष्ठ 20 रील वीडियो को प्रदर्शित किया गया। शीर्ष 10 विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया तथा सभी प्रतिभागियों को हुगली जिला पुलिस और आरामबाग महकमा पुलिस की ओर से प्रमाण पत्र दिए गए।

कार्यक्रम में हुगली जिला पुलिस अधीक्षक कामनाशीष सेन, आरामबाग एसडीपीओ सुप्रभात चक्रवर्ती, आरामबाग थाना प्रभारी राकेश सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हुगली जिला पुलिस अधीक्षक कामनाशीष सेन ने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया में पुलिस सीधे तौर पर शामिल नहीं थी। यह जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी गई थी। कुल 101 वीडियो प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि निर्णय जजमेंट के आधार पर हुआ है और इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। किसी प्रतियोगिता में कोई प्रथम आता है, कोई द्वितीय यह स्वाभाविक है। उन्होंने पहली बार इस आयोजन में आकर प्रसन्नता व्यक्त की।

बांकुड़ा में खेत की कीचड़ में मिला नवजात बच्ची का शव

बांकुड़ा : जिले के जयपुर थाना इलाके में गुरुवार को धान की रोपाई के दौरान किसानों ने खेत की कीचड़ भरी जमीन में आधा डूबा हुआ एक नवजात बच्ची का शव देखा। यह दृश्य देखकर किसान सन्न रह गए और पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय सूत्रों और पुलिस के अनुसार, इस दिन, सुबह में बांकुड़ा के जयपुर ब्लॉक अंतर्गत श्यामनगर ग्राम पंचायत के बेलिया डांगरपाड़ा गांव में कुछ किसान धान रोपने के लिए खेत में उतरे थे। इसी दौरान खेत के एक कोने में, सबमर्सिबल पंप के पास कीचड़ में उन्होंने नवजात बच्ची का शव पड़ा देखा। बच्ची का शरीर कीचड़ में आधा धंसा हुआ था। खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर जयपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कीचड़ से शव को बरामद किया। इसके बाद शव को जयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बाद में पोस्टमार्टम के लिए शव बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया। नवजात बच्ची को किसने, कब और किन हालात में खेत में फेंका, इसको लेकर फिलहाल रहस्य बना हुआ है। पुलिस आसपास के गांवों, स्थानीय नर्सिंग होम और स्वास्थ्य केंद्रों में जानकारी जुटा रही है।

अमेजन पर एआई-पावर्ड डिस्कवरी और अल्ट्रा-फास्ट डिलिवरी से वेलेंटाइन शॉपिंग में उछाल

कोलकाता, समाज्ञा : वेलेंटाइन डे से पहले अमेजन पर क्यूरेटेड सेलेक्शन, एआई-आधारित डिस्कवरी टूल्स और अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी विकल्पों ने खरीदारी को नई गति दी। कंपनी के अनुसार, चॉकलेट्स और ताजे फूल टॉप गिफ्टिंग चॉइस रहे, जिनमें 1.4 गुना सालाना वृद्धि दर्ज की गई। लक्जरी चॉकलेट्स और क्यूरेटेड हैम्पर्स जैसे प्रीमियम सेगमेंट में 1.3 गुना से अधिक वृद्धि देखी गई। अमेजन इंडिया के उपाध्यक्ष सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि जेन जेड और मिलेनियल ग्राहकों ने प्रीमियम और पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स में खास रुचि दिखाई। रुफस एआई टूल ने ग्राहकों को प्रोडक्ट खोजने, कीमत तुलना करने और रिव्यू पढ़ने में मदद की। फ्लॉवरऑरा और आईजीपी जैसे ब्रांड्स के 50, 24 और 12 लाल गुलाबों के पैक्स की मांग उल्लेखनीय रही।

पिता की पुण्यतिथि पर जरुरतमंद लोगों में भोजन वितरण

हावड़ा, समाज्ञा : कारोबारी नलिन विलोचन ने गुरुवार को अपने पिता स्व. उपेंद्रनाथ सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पर 150 से भी ज्यादा जरुरतमंद लोगों के प्रतिदिन होने वाले संध्याकालीन भोज के आयोजन में अपना सहयोग दिया। इस भोज का शुभारंभ हावड़ा रेलवे स्टेशन के आस-पास फुटपाथ पर रहनेवाले लोगों के लिए चलित वाहन पर हुआ और अंतिम पड़ाव के रूप में प्रतिदिन की भांति गंगा किनारे अवस्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में हुआ जहां स्व. उपेंद्रनाथ सिंह के पौत्र अर्पित ने अपने हाथों से सभी को भोजन करवाया।

श्री श्याम मंदिर घुसुड़ीधाम के 'रंग-रंगीला फाल्गुन मेला-2026' की तैयारियां जोरों पर

❑ **22 फरवरी को विराट निशान यात्रा, 25 को रजत निशान, 27-28 को मुख्य मेला, 4 मार्च को वृंदावन की होली**
❑ **लगेगा सवा लाख मैसूर पाक का महाभोग**
❑ **लाखाधिक भक्तों के समागम की संभावना, पुलिस प्रशासन व मंदिर प्रबंधन का व्यापक प्रबंध**

हावड़ा : कोलकाता में खाटूधाम के रूप में पूजित 'श्री श्याम मंदिर घुसुड़ीधाम' में वार्षिक रंग रंगीला फाल्गुन मेला-2026 की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। मनोकामना पूर्ति केन्द्र के रूप में परिणित हो चुके बाबा श्याम के इस पावन धाम श्री श्याम मंदिर घुसुड़ीधाम में निरंतर बढ़ रही बेशुमार भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस बार पुलिस प्रशासन मंदिर प्रबंधन के साथ काफी सक्रियता के साथ समन्वय करते हुए मेला के दौरान ऐसी व्यवस्था करने में तत्पर है कि मेला के दौरान यहां आने वाले लाखाधिक भक्तों को एकदम सुचारू रूप से उनके आराध्य के दर्शन-पूजन-अर्चन सुलभ हो सकें।

मेला के सुचारू संचालन के लिए मंदिर के प्रबंध न्यासी बिनोद टिबड़ेवाल की अध्यक्षता में 'घुसुड़ीधाम फाल्गुन मेला कमेटी-2026' का गठन किया गया है जिसमें चेयरपर्सन नवल सुलतानिया, सचिव सुरेन्द्र अग्रवाल, संयुक्त सचिव राधेश्याम टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष किशन कासुका, संयोजक वरूण अग्रवाल और कार्यक्रम समन्वयक कपिल अग्रवाल नियुक्त किये गए हैं। मंगलवार को इस संदर्भ में आयोजित बैठक के बाद मेला पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए मेला संयोजक वरूण अग्रवाल ने बताया कि हर वर्ष निकलने वाली घुसुड़ीधाम मंदिर की मुख्य निशान शोभायात्रा 22 फरवरी (रविवार) को घासबागान मैदान से घुसुड़ीधाम मंदिर तक आयोजित होगी जिसमें सैकड़ों श्रद्धालू रंग-बिरंगी ध्वजाओं के साथ लगभग 5 किलोमीटर लम्बे पैदल यात्रा मार्ग को तय करते हुए मंदिर में बाबा श्याम को ध्वजाएं अर्पित करेंगे जबकि मंदिर परिवार की ओर से 25 मार्च को घासबागान से घुसुड़ीधाम तक रजत निशान यात्रा के माध्यम से बाबा श्याम को चांदी का निशान व 111 मीटर लम्बा एक निशान भी बाबा श्याम को अर्पित किया जायेगा। मुख्य मेला यथा तिथि फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी, 27 व 28 फरवरी को अनुष्ठित होगा। इस अवधि में 27 फरवरी को सुबह मंगला आरती के साथ मंदिर के जो कपाट खुलेंगे वो 28 फरवरी की रात शयन आरती के पश्चात कपाट मंगल होंगे। कार्यक्रम समन्वयक कपिल अग्रवाल ने बताया कि इस अवधि में बाबा श्याम के दर्शन-पूजन-अर्चन के साथ ही मंदिर के कीर्तन संचालक मनोज अग्रवाल की देखरेख में भजनामृत वर्षा व अखंड ज्योति पाठ होगा जबकि बारस धोक-ज्योत व प्रसाद का कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा । मेला सचिव सुरेंद्र अग्रवाल और संयुक्त सचिव राधेश्याम टिबड़ेवाल ने बताया कि मेला के उपलक्ष्य में हमेशा की भांति 'सवा लाख' की श्रृंखला में इस बार 'सवा लाख मैसूर पाक' का महाभोग घुसुड़ीधाम परिवार की ओर से बाबा श्याम को अर्पित किया जायेगा और इसका वितरण मेला में आने वाले भक्तों में वितरित किया जायेगा। मेला अध्यक्ष बिनोद टिबड़ेवाल ने बताया कि मेला पर बाबा श्याम को सवामनी-छप्पन भोग अर्पित करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सम्पूर्ण व्यवस्था की गई है। मेला चेयरमैन नवल सुल्तानिया ने कहा कि यहां मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम सुविधा देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मेला का समापन कार्यक्रम 4 मार्च को वृंदावन की होली के साथ होगा। मंदिर के मिडिया प्रभारी सुरेश कुमार भुवालका और सोशल मिडिया प्रभारी देवेंद्र कासुका ने बताया कि जो भक्त विवशता और बाध्यता के कारण मेला में नहीं पहुंच सकेंगे उनको घर बैठे मेला का आनंद मिल सके, इसके लिए मंदिर की सोशल साइट्स के जरिए मेला के सीधे प्रसारण के प्रयास किये जा रहे हैं।

पानीहाटी में बस की टक्कर से दो की मौत, चार की हालत गंभीर

कोलकाता, समाज्ञा

उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में धानकल मोड के पास गुरुवार की सुबह एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सूत्रों के अनुसार, बीटी रोड पर दो बसों के चालकों के बीच आपसी रेस (रैश ड्राइविंग) चल रही थी। इसी दौरान, एक बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे साइकिल चला रहे दो लोगों को कुचल दिया। बस के पहियों के नीचे आने से दोनों साइकिल सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि साइकिल सवारों को टक्कर मारने के बाद बस एक ऑटो और एक बाइक से भी टकरा गई। इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सागर दत्त मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। पुलिस ने मौके से शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बस चालक की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

बिहार के विधानसभा अध्यक्ष समेत 45 विधायकों के निर्वाचन को उच्च न्यायालय में चुनौती

पटना: बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार समेत 45 सदस्यों के निर्वाचन को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत में पेश अधिवक्ता ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने बताया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से पराजित प्रत्याशियों ने ये चुनाव याचिकाएं दायर की हैं और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। प्रसाद ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''आम तौर पर कोई भी चुनाव याचिका सीधे खारिज नहीं की जाती। प्रतिवादियों को नोटिस भेजे जाते हैं और उपलब्ध सामग्री की जांच के बाद न्यायालय आदेश पारित करता है।' एक सवाल पर उन्होंने कहा, ''हां, गया टाउन सीट से प्रेम कुमार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। हालांकि, उनके मामले में अब तक नोटिस जारी नहीं हुआ है।' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आठवीं बार विधायक बने प्रेम कुमार के निर्वाचन को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले अखौरी ओंकार नाथ ने चुनौती दी है। वह 26 हजार से अधिक मतों से पराजित हुए थे। प्रसाद ने बताया कि अधिकतर चुनाव याचिकाएं विजयी उम्मीदवारों द्वारा दाखिल हलफनामों में कथित विसंगतियों या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों के आधार पर दायर की गई हैं। सूत्रों के अनुसार, जिन प्रमुख नेताओं के निर्वाचन को चुनौती दी गई है उनमें जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और युवा विधायक चेतन आनंद, तथा भाजपा के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा शामिल हैं। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक विधायक के निर्वाचन को भी चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। यह याचिका गोह सीट से 4,041 मतों के मामूली अंतर से विजयी रहे अमरेंद्र कुमार के निर्वाचन के खिलाफ दायर की गई है।

वाराणसी में गंगा पर चल रहे सभी सरकारी और निजी क्रूज़ तय नियमों का पालन कर रहे हैं: मंत्री

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि वाराणसी में गंगा नदी पर चल रहे सभी सरकारी और निजी क्रूज निर्धारित मानदंडों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। मंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और तथ्यों की अनदेखी कर प्रश्न उठाना उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने वाराणसी में गंगा नदी पर चल रहे सरकारी व निजी क्रूज की संख्या, उनके संचालन के मानक तथा संबंधित विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग की थी। मंत्री ने विस्तृत उत्तर देते हुए विपक्ष पर पर्याप्त जानकारी के अभाव में सवाल खड़े करने का आरोप भी लगाया। सदस्य ने पूछा कि जनपद वाराणसी में कितने सरकारी और निजी क्रूज संचालित हो रहे हैं, उनके संचालन के मानक क्या हैं और क्या इसका विवरण सदन के पटल पर रखा जाएगा? इसके जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि वाराणसी में पांच सरकारी और दो निजी क्रूज संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनके संचालन के मानक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। चर्चा के दौरान आशुतोष सिन्हा ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थिति पर अतिरिक्त जानकारी मांगी।

बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग ठुकराई

पटना: बिहार सरकार ने बृहस्पतिवार को करीब एक दशक पुराने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून सभी दलों को साथ लेकर राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद, जो सत्तारूढ़ राजग का हिस्सा हैं, ने नीति की समीक्षा की मांग करते हुए कहा था कि इससे राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह कानून राज्य विधानमंडल में सभी दलों को साथ लेकर पारित किया गया था और इसकी समीक्षा का कोई सवाल ही नहीं उठता। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी समीक्षा की मांग को खारिज करते हुए कहा कि इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

बिहार के सभी पंचायतों के खेल क्लब व आउटडोर स्टेडियम में सीसीटीवी कैमरे लगाएं: मुख्य सचिव

पटना: बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बृहस्पतिवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी पंचायतों में स्थित खेल क्लब तथा सभी खेल परिसरों और आउटडोर स्टेडियम में पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। मुख्य सचिव ने खेल विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) द्वारा जारी बयान के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य के खेल तंत्र में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि खेल क्लबों के संचालन और प्रगति की व्यवस्थित निगरानी के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत निगरानी ढांचा विकसित किया जाए।

बिहार में बिना आवश्यक अनुमति वाले 'डीजे' वाहनों के खिलाफ चलेगा अभियान : मंत्री

पटना: बिहार सरकार राज्य में बिना अनुमति संचालित हो रहे 'डीजे' (बड़े म्यूजिक सिस्टम) लगे वाहनों के खिलाफ अगले 15 दिनों के भीतर व्यापक जांच अभियान चलाएगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बृहस्पतिवार को विधान परिषद में यह जानकारी दी। बजट सत्र के दौरान निर्दलीय विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि जिन 'डीजे' वाहनों के पास आवश्यक अनुमति नहीं होगी, उन्हें संचालित होने से रोका जाएगा तथा जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। ब्रजवासी ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य में कई 'डीजे' वाहनों की संरचना इस तरह से बदल दी गई है कि उनके पंजीकरण नंबर छिप जाते हैं। उन्होंने इसे नियमों का उल्लंघन बताया। 'डीजे' वाहन आमतौर पर एम्प्लीफायर, मिक्सर और अत्यधिक तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्पीकर से लैस होते हैं।

गोरखपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ीं, 9 अन्य की दृष्टि चली गई

गोरखपुर (उप्र): शहर के एक निजी अस्पताल में एक नेत्र शिविर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद संक्रमण होने से नौ मरीजों की एक आंख निकालनी पड़ी और नौ अन्य मरीजों की एक आंख की रोशनी चली गई। अधिकारियों ने अस्पताल को सील कर जांच के आदेश दिये हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में एक फरवरी को आयोजित नेत्र शिविर के दौरान 30 मरीजों का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के 24 घंटों के भीतर, कई मरीज गंभीर दर्द और ऑपरेशन वाली आंख से स्राव होने की शिकायत करने लगे। अधिकारियों ने पुष्टि की कि कम से कम 18 लोगों में संक्रमण विकसित हुआ और उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के उच्च केंद्रों में रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि एक मरीज़ की आंख की रोशनी हालांकि बाद में आंशिक रूप से वापस आ गई। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि अस्पताल को सील कर दिया गया है और मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री 28 फरवरी को अजमेर में 23,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करेंगे

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 फरवरी को अपने अजमेर दौरे के दौरान 23,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बृहस्पतिवार को अजमेर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। राठौड़ ने कहा, 'यह एक सरकारी कार्यक्रम होगा और सरकार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रही है। मैं यहां यह सुनिश्चित करने आया हूं कि जनता को कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।'' राठौड़ ने कहा प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान 23,500 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तथा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में होने वाले कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए।

बिहार में अल्पसंख्यक कार्य विभाग के 'चिंतन शिविर' का रीजीजू ने किया उद्घाटन

पटना: केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में अल्पसंख्यक कार्य विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' का उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन की उपस्थिति में रीजीजू ने हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों के लिए 'हज रिस्ट बैंड' और 'हज सुविधा ऐप' सहित विभाग के एआई चैटबॉट जैसी कई सुविधाओं की शुरुआत की। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रीजीजू ने मंत्रालय की 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' (पीएमजेवीके) योजना के तहत 'निगरानी ऐप' भी लॉन्च किया।

यूपी के दोनों उपमुख्यमंत्री संतों और बटुकों का सम्मान करते हैं : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

वाराणसी/लखनऊ: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री संतों और बटुक ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 40 दिनों के भीतर गाय को 'राष्ट्र माता' घोषित नहीं किया गया तो संत लखनऊ तक मार्च करेंगे। वाराणसी में पत्रकारों से बात करते हुए, अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में हाल में संपन्न माघ मेले के दौरान हुए उस विवाद के संबंध में उपमुख्यमंत्रियों - ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य - की हालिया टिप्पणियों का जिक्र किया, जहां कुछ बटुकों के साथ सुरक्षा कर्मियों द्वारा कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया था। उन्होंने कहा कि पाठक ने बटुकों की चोटी को कथित तौर पर खींचने को 'गंभीर पाप' करार दिया था और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। अविमुक्तेश्वरानंद ने मौर्य की पिछली अपील का भी जिक्र किया जिसमें उनसे अपना विरोध समाप्त करने और मौनी अमावस्या पर संगम में पवित्र स्नान करने का आग्रह किया गया था। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, 'दोनों उपमुख्यमंत्री समाज में अपनी स्थिति के प्रति सचेत हैं और उन्होंने दिखाया है कि वे बटुकों और संतों का सम्मान करते हैं।' उन्होंने कहा कि पाठक के अपने लखनऊ आवास पर 101 बटुकों के लिए अनुष्ठान करने के निर्णय ने इस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया।

राहुल गांधी और 25 कांग्रेस सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति हिरासत में

जयपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दल के 25 अन्य सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाला वीडियो जारी करने वाले एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को राजस्थान के कोटा में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। कोटा की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी को बोरखेड़ा थाने में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा, अभी तक किसी भी संगठन से उनके संबंधों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उद्योग नगर पुलिस थाने में उनके खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। संबंधित धाराओं के तहत उचित कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

यूपी एटीएस ने 31 वर्षों से फरार आतंकी को गिरफ्तार किया

लखनऊ: प्रतिबंधित खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) से जुड़े एक आतंकवादी को उत्तर प्रदेश आतंकवाद-रोधी दस्ता (एटीएस) और नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। वह 1995 में जमानत मिलने के बाद से फरार था। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान सुखविंदर सिंह ढिल्लों उर्फ दयाल सिंह उर्फ राकेश शर्मा छिंदा के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से पंजाब के कपूरथला का रहने वाला है। उसे 18 फरवरी को मोहाली जिले से पकड़ा गया, जहां वह छिपा हुआ था। अधिकारियों के अनुसार, ढिल्लों कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन का सक्रिय सदस्य था और गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर-20 पुलिस थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में वांछित था। ढिल्लों को अप्रैल 1993 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब उसके कब्जे से एके-56 राइफल और 121 कारतूस मिले थे, और बाद में दिसंबर 1993 में अदालत ने उसे जमानत दे दी थी। अधिकारियों ने बताया कि जमानत मिलने के बाद ढिल्लों कुछ मौकों पर अधिकारियों के सामने पेश हुआ, लेकिन 16 अगस्त 1995 से वह फरार हो गया।

फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

संभल (उप्र): आगामी फिल्म ''यादव जी की लव स्टोरी'' के निर्माताओं और अभिनेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व गुन्नौर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक अजीत कुमार राजू यादव ने किया और बहजोई में जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने बाद में जिला मजिस्ट्रेट को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की गई। बुधवार को पुलिस ने बीएनएस की प्रासंगिक धाराओं के तहत फिल्म के निर्माता, निर्देशक और मुख्य अभिनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें शिकायत की गई है कि फिल्म की विषयवस्तु से समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है और सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को सिंगापुर, जापान की यात्रा पर जाएंगे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को सिंगापुर और जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। बृहस्पतिवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में कई बैठकों और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य निवेश संबंधों को मजबूत करना है। बयान में कहा गया है कि 25 से 26 फरवरी तक आदित्यनाथ जापान में रहेंगे, जहां वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बयान में कहा गया कि जापान की अत्याधुनिक 'मैग्लेव' (मैग्नेटिक लेविटेशन) ट्रेन की यात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का विशेष आकर्षण बनने जा रही है। ये ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है।

मथुरा : कार नहर में गिरी, तीन भाइयों समेत चार लोगों की मौत

मथुरा (उप्र): मथुरा जिले के मोगर्रा इलाके में एक अनियंत्रित कार के नहर में गिर जाने से उसमें सवार तीन भाइयों समेत चार लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को दी। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) सुरेश चंद्र रावत ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार की रात महमूदपुर से डीग जा रही एक कार मोगर्रा थाना क्षेत्र के नहला देविया पुल के नजदीक एक तीव्र मोड़ के पास अनियंत्रित होकर एक ढांचे से टकरा गई और नहर में गिर गई। रावत ने कहा कि दो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कार को नहर से बाहर निकालने में कामयाब रहे लेकिन उसमें सवार लोगों को बचाया नहीं जा सका। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रावत ने बताया कि मृतकों की पहचान महावन थाना क्षेत्र के बल्देवगढ़ निवासी राहुल (23) और उसके चचेरे भाई अमित (23) और मोहित (21) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि हादसे में 20 साल के एक अन्य युवक की भी मृत्यु हुई है और उसकी पहचान करने के प्रयास किया जा रहे हैं। रावत ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1989 में हत्या के दोषी व्यक्ति को बरी किया

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1987 में फर्रुखाबाद में हुई एक हत्या के मामले में 1989 में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने बुधवार को व्यवस्था दी कि अधीनस्थ अदालत द्वारा 17 मई 1989 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दर्ज की गई सजा और दोषसिद्धि त्रुटिपूर्ण थी और इसे रद्द किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, अधीनस्थ अदालत के समक्ष इस मामले में तीन आरोपी थे, जिनमें से एक को दोषी ठहराया गया जबकि समान साक्ष्यों के आधार पर दो अन्य को बरी कर दिया गया। अपने निर्णय में उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता जेल में बंद खुन्नी लाल यदि किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

रमजान में सहरी और इफ्तार के वक्त मस्जिदों से लाउडस्पीकर से ऐलान पर सरकार ने स्पष्ट किया रुख

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने रमजान के महीने में 'सहरी' और 'इफ्तार' के वक्त मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिये ऐलान के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि ऐलान की यह परम्परा उस वक्त की है जब घड़ियों का चलन नहीं था और उच्चतम न्यायालय ने लाउडस्पीकर बजाने की अवधि पर स्पष्ट आदेश दिये हैं, जो लागू हैं। विधानसभा में शून्य काल के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य कमाल अख्तर ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ष सभी त्यौहार जैसे होली, दीवाली, दशहरा, कांवड़ यात्रा तथा ईसाई और सिख धर्मों के उत्सव होते हैं और आज से मुसलमानों का रमजान का पाक महीना शुरू हुआ है।

लखनऊ में सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी को गोली मारने के दो आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में हाल ही में आपसी विवाद को लेकर एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) निपुण अग्रवाल ने बताया कि विगत 30 जनवरी को सेवानिवृत्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवधेश पाठक को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित मिश्रा और उसके भाई दुर्गेश मिश्रा को सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के झिझिलापुरवा इलाके से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गये आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गयी है। अग्रवाल ने बताया कि आरोपी अमित मिश्रा पिछले साल नवंबर में हुए एक झगड़े के बाद पाठक से रंजिश रखता था। उन्होंने बताया कि पिछले साल नवंबर में मोटरसाइकिल चलाते समय हुए झगड़े में सेवानिवृत्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट पाठक ने कथित तौर पर मिश्रा को गाली दी थी और थप्पड़ मारा था। अग्रवाल ने बताया कि उस समय तो मामला शांत हो गया था लेकिन मिश्रा ने कथित तौर पर बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि इस साल 30 जनवरी को सुशांत गोल्फ सिटी इलाके के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास मिश्रा रास्ता पूछने के बहाने पाठक के पास गया और उनके सिर में गोली मार दी और अपने बड़े भाई दुर्गेश मिश्रा के साथ मोटरसाइकिल पर मौके से भाग गया।

एप्स्टीन विवाद के बाद बिल गेट्स की फाउंडेशन से नाता तोड़ें : राजद सांसद की नीतीश से मांग

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की अध्यक्षता वाली 'गेट्स फाउंडेशन' से राज्य सरकार के संबंध समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में गेट्स का नाम सामने आया है। पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान में बक्सर से लोकसभा सदस्य सिंह ने 17 फरवरी को लिखे अपने पत्र को सोशल मीडिया पर साझा किया है। पत्र में सिंह ने कहा है कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गेट्स फाउंडेशन बिहार सरकार के साथ नीतिगत मामलों में कार्य कर रही है और यह सहयोग ''कुछ मामलों में अधिकृत तथा कुछ में अनधिकृत'' है। सिंह ने आरोप लगाया कि गेट्स फाउंडेशन द्वारा नियुक्त और प्रति माह लाखों रुपये वेतन पाने वाले कुछ लोगों को बिहार के कई वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है। राजद नेता ने कहा कि इससे उन्हें सरकार की योजनाओं और नीतियों से जुड़ी सूचनाओं तक आसान पहुंच मिलती है।

कानपुर पुलिस ने नौ राज्यों में फैले फर्जी डिग्री गिरोह का भंडाफोड़, चार सदस्य गिरफ्तार

कानपुर : कानपुर पुलिस ने कम से कम नौ राज्यों में सक्रिय फर्जी डिग्री उपलब्ध कराने वाले एक संगठित गिरोह का बृहस्पतिवार को भंडाफोड़ कर चार लोगों को गिरफ्तार किया और 14 विश्वविद्यालयों से जुड़े लगभग 900 जाली अंकपत्र व दस्तावेज जब्त किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि आरोपी यहां किदवई नगर स्थित 'शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन' नामक कार्यालय से यह गिरोह संचालित कर रहे थे। गिरोह कथित तौर पर उम्मीदवारों को परीक्षा दिए बिना हाईस्कूल (10वीं) से लेकर बीटेक, बी फार्म और एलएलबी जैसे पाठ्यक्रमों तक के अकादमिक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराता था। बरामद जाली दस्तावेजों में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की 357 फर्जी डिग्रियां शामिल हैं, जो किसी एक संस्थान से जुड़ी सबसे अधिक संख्या है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के कई निजी विश्वविद्यालयों के नाम पर जारी जाली प्रमाणपत्र भी बरामद किए। पुलिस के अनुसार, एमएससी स्नातक और गणित शिक्षक एवं कथित सरगना शैलेन्द्र कुमार (36) पहले छात्रों को निजी परीक्षा फॉर्म भरने में मदद करता था और बाद में फर्जी डिग्री के कारोबार में उतर गया। उसने कथित तौर पर विश्वविद्यालयों के लिपिकों और कर्मचारियों का नेटवर्क बना लिया था, जो मांग पर असली मार्कशीट और प्रमाणपत्र उपलब्ध कराते थे।

बिहार सरकार 45 हजार और शिक्षकों की करेगी नियुक्ति : शिक्षा मंत्री

पटना: बिहार सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि वह आगामी महीनों में शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई-4) के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में 45,000 और शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके अलावा, सरकार राज्य संचालित दिव्यांग विद्यार्थियों के विद्यालयों के लिए 7,000 विशेष शिक्षकों की भी नियुक्ति करेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षा विभाग के 60,204.60 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट पर चर्चा के समापन के दौरान विधानसभा में यह घोषणा की। सदन ने विभाग के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया, हालांकि विपक्ष के सभी सदस्य सरकार के जवाब से असंतुष्टी जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। मंत्री ने कहा, सरकार ने आगामी महीनों में टीआरई-4 के माध्यम से 45,000 और शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। टीआरई-1 और टीआरई-2 में क्रमशः 1.70 लाख से अधिक और 70,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जबकि टीआरई-3 में 66,603 पदों को भरा गया।' उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से अब तक बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से टीआरई के तहत 2.58 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। मंत्री ने बताया कि इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त 3.68 लाख गैर-आयोग शिक्षकों का नियमितीकरण भी किया गया है। बीपीएससी राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। मंत्री ने कहा, सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। मॉडल स्कूलों के निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये तथा पुराने शिक्षण संस्थानों को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।' चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि राज्य की राजग सरकार सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधारभूत संरचना में सुधार करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार के लिए आवंटित धन का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है और शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

गुजरात के डीजीपी भारत-पाकिस्तान सीमा और कच्छ के तटीय क्षेत्र में सुरक्षा की समीक्षा करेंगे

अहमदाबाद : गुजरात के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के.एल.एन. राव 21 और 22 फरवरी को भुज में एक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे जिसमें भारत-पाकिस्तान सीमा और कच्छ के तटीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। वे भारत-पाकिस्तान सीमा और कच्छ के तटीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि 'अपराध सम्मेलन' में राज्य पुलिस विभाग के अधिकारी, भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

बांग्लादेश ने बकाया राशि के कारण स्पाइसजेट को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोका

नयी दिल्ली : बांग्लादेश ने स्पाइसजेट को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया है क्योंकि बजट एयरलाइन ने अभी तक बकाया भुगतान नहीं किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। बांग्लादेशी हवाई क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण, एयरलाइन कोलकाता से गुवाहाटी सहित कुछ उड़ानों के लिए लंबे मार्ग अपना रही है। संपर्क करने पर, स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि एयरलाइन परिचालन और प्रक्रियात्मक मामलों पर संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है, जिसमें दिशा-निर्देशन संबंधी शुल्क भी शामिल हैं। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ''ये उद्योग से जुड़े सामान्य मुद्दे हैं और हम इनका शीघ्र समाधान निकालने के लिए रचनात्मक रूप से काम कर रहे हैं। हमारी उड़ान सेवाएं अप्रभावित हैं और हम नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी निर्धारित सेवाएं जारी रखे हुए हैं।''

नवीनतम समीक्षा में भारत में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर सात रह गई

नयी दिल्ली : वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों की एक नई समीक्षा के बाद देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या आठ से घटकर सात रह गई है। यह बदलाव केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने की घोषणा के अनुरूप है। 'पीटीआई-भाषा' को अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने हाल में नौ फरवरी से प्रभावी सभी नक्सल प्रभावित राज्यों का नया वर्गीकरण जारी किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 'एलडब्ल्यूई से निपटने की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' की व्यापक समीक्षा की, जिसमें झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल सहित नौ राज्यों के 38 जिलों का विश्लेषण किया गया।

ईडी ने अनिल अंबानी को 26 फरवरी को पेश होने के लिए ताजा समन जारी किया

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के इस सप्ताह उसके समक्ष उपस्थित नहीं होने के बाद उन्हें 26 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने का ताजा समन जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उनकी पत्नी और पूर्व अभिनेत्री टीना अंबानी भी ईडी द्वारा दूसरी बार समन जारी किए जाने के बावजूद 17 फरवरी को एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थीं। उन्हें संघीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए पहला समन 10 फरवरी को जारी किया गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं जिसके बाद उन्हें नया नोटिस दिया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि ईडी ने उन्हें भी अगली तारीख दी है या नहीं।

उच्चतम न्यायालय ने फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को जमानत दी

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में दर्ज करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बृहस्पतिवार को फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को जमानत दे दी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को इस मामले में पहले दी गई अंतरिम जमानत को भी नियमित कर दिया।

मुर्मू ने स्लोवाकिया, सर्बिया और एस्टोनिया के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की

नयी दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को यहां राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया, सर्बिया और एस्टोनिया के राष्ट्रपतियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर चर्चा हुई। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी का स्वागत किया और पिछले वर्ष देश की अपनी राजकीय यात्रा को याद किया। उन्होंने खुद के वहां हुए सौहार्दपूर्ण स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए पेलेग्रिनी

को धन्यवाद दिया। मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी में जारी 'एआई इम्पैक्ट समिट' में पेलेग्रिनी की भागीदारी की सराहना की और इसे भारत और दुनिया के लिए एक निर्णायक क्षण बताया, जो लोग, ग्रह और प्रगति के सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में कहा गया है, राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 'जनहित के लिए प्रौद्योगिकी' के सिद्धांत पर काम कर रहा है और इसी दिशा में 'एआई इम्पैक्ट समिट' का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सभी के लिए सुलभ और लाभकारी बनाना है। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ अपनी मुलाकात में मुर्मू ने जून 2023 में देश की अपनी यात्रा को स्नेहपूर्वक याद किया और उन्हें और सर्बियाई सरकार को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। मुर्मू के हवाले से बयान में कहा गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सर्बिया और भारत दोनों की दक्षता को देखते

जम्मू-कश्मीर में लगभग 13,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं: शिक्षा मंत्री

जम्मू : शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में शिक्षकों के 12,977 पद रिक्त हैं और स्कूल शिक्षा विभाग ने 2024 के बाद से किसी भी स्कूल का उन्नयन नहीं किया है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक शक्ति राज परिहार द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि जम्मू मंडल में 7,985 और कश्मीर मंडल में शिक्षकों के 4,992 पद रिक्त हैं। जिलावार आंकड़ों के अनुसार, जम्मू मंडल में राजौरी (1,416), कठुआ (1,332), जम्मू (1,234) और पुंछ (946) उन जिलों में शामिल हैं जहां सबसे अधिक रिक्तियां हैं, जबकि कश्मीर मंडल में अनंतनाग (1,016), बडगाम (797), पुलवामा (764) और कुपवाड़ा (621) में सबसे अधिक रिक्तियां हैं।

नौसेना सूचना लीक मामला: चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया गया

उडुपी (कर्नाटक) : भारतीय नौसेना से संबंधित गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को कथित रूप से हस्तांतरित करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिससे गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या चार हो गई है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान अलिफ इस्लाम (21) के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल का मूल निवासी है और वर्तमान में केरल के इडुक्की जिले के मरायूर गांव में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि उसे भारतीय नौसेना के जहाजों के पहचान क्रमांक वाली गोपनीय सूची की कथित जानकारी लीक करने के संबंध में गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपियों पर बिना अनुमति के व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान में अपने संपर्कों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का संदेह है। अधिकारियों ने बताया कि नौसेना से संबंधित डेटा को अवैध रूप से साझा करने की शिकायत के बाद 2025 में मालपे पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि जांच भारतीय नौसेना से जुड़े जहाजों के नंबरों की एक गोपनीय सूची के कथित रूप से साझा किए जाने से संबंधित है। नवंबर 2025 में, उत्तर प्रदेश के दो आरोपियों - रोहित और संत्री - को इसी मामले में हिरासत में लिया गया था। बाद में, दिसंबर 2025 में गुजरात के हीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। हाल में की गयी गिरफ्तारी के साथ, इस मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या बढ़कर चार हो गई है।

न्यायालय ने कफ सिरप बनाने वाली कंपनी से पूछा

क्या आपको पता है कि देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचा

नयी दिल्ली : जिस फार्मास्युटिकल कंपनी के कफ सिरप के सेवन से उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर 18 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी, उससे उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पूछा, ''क्या आपको पता है कि इससे देश की छवि को कितना नुकसान हुआ है?'' प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने उस आदेश को रद्द करने से मना कर दिया, जिसमें कंपनी और उसके कुछ अधिकारियों को एक शिकायत पर तलब किया गया था, जिसमें मानक रहित दवाओं के विनिर्माण और बिक्री सहित कई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। पीठ ने कहा, ''सिर्फ पैसों के लिए, आप इसमें शामिल हुए? इससे देश की छवि खराब हुई है।'' कंपनी और उसके अधिकारियों के वकील ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि सिरप पीने से किसी की मौत हुई है। पीठ ने पूछा, ''क्या आपको पता है कि इससे देश की छवि को कितना नुकसान हुआ है?'' शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें कंपनी और उसके कुछ अधिकारियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। इन अधिकारियों ने गौतम बुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जनवरी 2024 के समन के आदेश को चुनौती दी थी।

एनजीओ हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहा है, जो चिंताजनक है: एनएचआरसी

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने कुछ गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा ''उसके नाम और लोगो का दुरुपयोग'' किए जाने के मामले का संज्ञान लिया और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है। ये एनजीओ ऐसे नामों से पंजीकृत हैं जो एनएचआरसी के नाम से मिलते जुलते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि इस तरह के ''भ्रामक नामों का जारी रहना जनता के विश्वास को कम कर सकता है, जनादेश के दुरुपयोग, धन के संभावित गबन और सरकारी संस्थाओं के लिए एनएचआरसी जैसे वैधानिक निकाय तथा गैर-सरकारी संगठनों के बीच अंतर करने में भ्रम पैदा कर सकता है।'' मानवाधिकार आयोग ने कहा कि उसने पहले भी विभिन्न मंचों के माध्यम से ''अपने नाम और लोगो के दुरुपयोग'' के संबंध में चिंता व्यक्त की थी और संबंधित अधिकारियों को ऐसे ''संदिग्ध संगठनों'' के पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सूचित किया था। हालांकि, बयान में कहा गया है कि उल्लंघन के मामले लगातार उसके संज्ञान में आते रहते हैं। एनएचआरसी ने कहा कि उसे देश भर में व्यक्तिगत शिकायतकर्ताओं के साथ-साथ एनजीओ से भी मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही हैं। बयान में कहा गया, ''इन शिकायतों की जांच करते समय आयोग ने पाया है कि कई एनजीओ ने एनएचआरसी के नाम से भ्रामक रूप से मिलते-जुलते नामों से अपना पंजीकरण कराया है।'' बयान में कहा गया, ''हाल ही में आयोग को 'राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद (एनएचआरसी)' के नाम से पंजीकृत एक गैर-सरकारी संगठन के बारे में पता चला, जो कथित तौर पर 2022 में दिल्ली सरकार के तहत पंजीकृत है। इसकी प्रचार सामग्री में दावा किया गया है, ''नीति आयोग द्वारा पंजीकृत'', ''कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा पंजीकृत'', ''भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन पंजीकृत'' और ''आंध्र प्रदेश मानवाधिकार परिषद संघ'' से संबद्ध।

नीरज पांडे ने 'घूसखोर पंडत' का शीर्षक वापस लिया, न्यायालय ने याचिका का निपटारा किया

नयी दिल्ली : फिल्म निर्माता नीरज पांडे द्वारा 'घूसखोर पंडत' शीर्षक एवं उससे जुड़ी सभी प्रचार सामग्री वापस लिए जाने की जानकारी दिए जाने के बाद, उच्चतम न्यायालय ने इस फिल्म के खिलाफ दायर याचिका का बृहस्पतिवार को निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पांडे के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने के बाद याचिका का निपटारा किया और उम्मीद जताई कि यह विवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यह याचिका 'ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया' के राष्ट्रीय संगठन सचिव अतुल मिश्रा ने दायर की थी और इसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया गया था। पांडे ने अपने हलफनामे में कहा कि मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म का नया शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन यह पहले वाले नाम से मिलता-जुलता नहीं होगा। उन्होंने कहा, ''मैं आदर पूर्वक अवगत कराता हूं कि पहले के शीर्षक 'घूसखोर पंडत' को स्पष्ट रूप से वापस ले लिया गया है और इसका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं किया जाएगा।

अमेरिका नीत रणनीतिक गठबंधन 'पैक्स सिलिका' में शुक्रवार को शामिल हो सकता है भारत

नयी दिल्ली : अमेरिका नीत रणनीतिक गठबंधन 'पैक्स सिलिका' में भारत के आधिकारिक तौर पर शामिल होने की उम्मीद है। इसका मकसद महत्वपूर्ण खनिजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक मजबूत आपूर्ति शृंखला बनाना है। यह कदम दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और रिश्तों में तनाव के बाद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई अन्य पहलों पर आगे बढ़ने की कोशिशों के बीच आया है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि भारत शुक्रवार को 'पैक्स सिलिका' पहल में आधिकारिक रूप से शामिल हो सकता है। यह पहल महत्वपूर्ण खनिजों और एआई के लिए सुरक्षित, मजबूत तथा नवाचार आधारित आपूर्ति शृंखला बनाने के लिए दिसंबर में शुरू की गई थी। पैक्स सिलिका सम्मेलन 12 दिसंबर को वाशिंगटन में हुआ था, जहां साझेदार देशों ने पैक्स सिलिका घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने पिछले महीने नई दिल्ली को रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की घोषणा की।

योग शिविर के लिए शुल्क: न्यायालय ने पतंजलि ट्रस्ट की सुधारात्मक याचिका खारिज की

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की सुधारात्मक याचिका को खारिज कर दिया और न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि आवासीय और गैर-आवासीय दोनों प्रकार के योग शिविरों के आयोजन के लिए प्रवेश शुल्क लेने पर ट्रस्ट को सेवा कर का भुगतान करना होगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सुधारात्मक याचिका पर विचार करते हुए इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई मामला नहीं बनता है। पीठ ने चार फरवरी को यह आदेश दिया जिसे बृहस्पतिवार को अपलोड किया गया। पीठ ने कहा, ''हमने सुधारात्मक याचिका और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन कर लिया है। हमारी राय में, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य (2002) के मामले में इस न्यायालय द्वारा इंगित मापदंडों के भीतर सुधारात्मक याचिका पर विचार करने का कोई मामला नहीं बनता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी के लिए प्रतिबद्धता जताई है: सिन्हा

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बृहस्पतिवार को कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय की पूरी गरिमा और सुरक्षा के साथ घाटी में वापसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया एक वादा है। उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी तंत्र ने सच्चाई को दबाने की कोशिश की, लेकिन आतंक फैलाने वाले और पीढ़ियों की आत्माओं पर प्रहार करने वाले आतंकवादियों और उनके समर्थक नेटवर्क को कभी माफ नहीं किया जाएगा और न ही भुलाया जाएगा। प्रोफेसर अशोक कौल द्वारा लिखित पुस्तक 'कश्मीर-नेटिविटी रीगेन्ड' के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा, ''कश्मीरी पंडितों

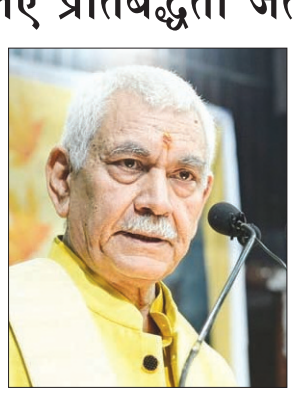

की पूर्ण गरिमा और सुरक्षा के साथ वापसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता है।'' उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा, ''केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के सपनों और भविष्य को नष्ट करने की शत्रु की नापाक साजिश को निर्णायक रूप से विफल कर दिया गया है। अथक प्रयासों से इस भूमि की प्राचीन महिमा को पुनर्स्थापित किया गया है और विकास को गति दी गई है। बहुत जल्द, यह धरती आतंकवाद के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी।'' उपराज्यपाल ने कहा, ''मैं कश्मीरी पंडित समुदाय के अदम्य साहस को सलाम करता हूं। विस्थापित प्रत्येक परिवार अपने भीतर कश्मीर की जीवंत चिंगारी लिए हुए था। संघर्ष और कठिनाइयों की अग्निपरीक्षा में भी उन्होंने दर्शन, आध्यात्मिकता, संस्कृति, भाषा और परंपराओं को संरक्षित रखा। पीड़ा के बीच भी उन्होंने संभावनाओं को उजागर किया और सफलता की नयी ऊंचाइयों को छुआ।

'एआई इम्पैक्ट समिट 2026' ने नये युग के लिए नैतिक दिशा तय की: अमित शाह

नयी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' ने नरेन्द्र मोदी सरकार के तहत हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर देश को एक नये युग में नेतृत्व के लिए तैयार किया है। शाह ने 'एक्स' पर की गई कई पोस्ट में कहा कि वैश्विक नेताओं और तकनीकी दिग्गजों के सबसे बड़े सम्मेलन की मेजबानी करके, भारत ''सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के प्राचीन मंत्र के साथ नये युग के लिए नैतिक दिशा तय कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन ''भारत का दुनिया से किया गया ऐसा वादा है, जिसके माध्यम से वह अपनी नवाचार की असीम क्षमता और संस्कृति में गहराई तक रची-बसी लोकतांत्रिक भावना के बल पर मानवता की प्रगति की यात्रा को निरंतर गति प्रदान करेगा।''उन्होंने कहा, ''भविष्य भले ही कई लोगों के लिए अनिश्चित हो, लेकिन भारत ने पहले ही अपने भाग्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली है।''शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सम्मेलन में प्रस्तुत भारत की एआई परिकल्पना मानवता को एक त्रुटिरहित भविष्य की ओर दिशा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि नैतिकता, जवाबदेही, राष्ट्रीय डाटा संप्रभुता, सुलभता और विश्वसनीय प्रणालियों के सिद्धांतों के साथ दुनिया सभ्यतागत छलांग लगाने के लिए तैयार है।उन्होंने कहा, ''इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रदर्शित सर्वम एआई इस बात का प्रमाण है कि भविष्य भारत का है। बाईस भारतीय भाषाओं में अत्याधुनिक एआई समाधान प्रदान करते हुए, यह सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकी हर व्यक्ति तक पहुंचे, जिससे मोदी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होता है, जहां प्रौद्योगिकी नागरिकों की भरोसेमंद सहयोगी है।''

कश्मीर : राजौरी में दो विदेशी पिस्तौल बरामद, आतंकी सहयोगी गिरफ्तार

जम्मू : जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तान स्थित आकाओं से सीधे संबंध रखने वाले एक आतंकी सहयोगी को दो विदेशी पिस्तौल बरामद किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि नियंत्रण रेखा के पास स्थित सैर गांव निवासी सचिन कुमार उर्फ पम्मा को पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के संयुक्त अभियान में बुधवार देर रात नौशेरा सेक्टर के एक गांव से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि कुमार की गिरफ्तारी के साथ ही एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, जो प्रारंभिक जांच के अनुसार, पाकिस्तान के मादक पदार्थ और हथियार तस्करों के संपर्क में था।

उन्होंने बताया कि कुमार के पास से दो पिस्तौल बरामद की गईं, जिसमें से एक तुर्की और दूसरी चीन निर्मित थी। इसके साथ ही चार मैगज़ीन और 15 गोलियां भी बरामद की गईं। इससे पहले, अधिकारियों ने बताया कि बुधवार देर रात नौशेरा के रायपुर गांव में सेना के गश्ती दल ने आरोपी को रोका और गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच की जा रही है।

अदालत ने पालतू कुत्ते को साझा तरीके से पालने की अर्जी पर देहाद्राई को नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दाखिल एक याचिका पर उनके पूर्व मित्र एवं वकील जय अनंत देहाद्राई को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मोइत्रा ने अपनी याचिका में जिला न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें हेनरी नामक पालतू रॉटवीलर कुत्ते का साझा संरक्षण देने से इनकार कर दिया गया था। देहाद्राई ने दलील दी कि मोइत्रा की याचिका इसी स्तर पर खारिज कर दी जानी चाहिए। मोइत्रा ने उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में कहा कि नवंबर 2025 में पारित अंतरिम आदेश में, जिला न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि हेनरी को उन्हें उनके पालतू जानवर के रूप में दिया गया था और

वह आमतौर पर उनके साथ उनके आवास पर रहता था। याचिका में तृणमूल सांसद ने कहा कि जिला अदालत के आदेश ने उन्हें उस पालतू जानवर के प्यार और स्नेह से वंचित कर दिया जिसे उन्होंने दो साल तक पाला था। उन्होंने आरोप लगाया, ''अपीलकर्ता भी हेनरी के संरक्षक थे। हेनरी मुख्य रूप से अपीलकर्ता के आवास पर रहता था, जहां से उसे कथित तौर पर प्रतिवादी द्वारा तब ले जाया गया जब वह अनधिकृत रूप से उनके घर में प्रवेश कर रहे थे।'' जिला अदालत का अंतरिम आदेश मोइत्रा द्वारा दायर एक याचिका पर आया था, जिसमें उसने पालतू कुत्ते की साझा अभिरक्षा के लिए अपने और देहाद्राई के बीच हुए मौखिक समझौते के विशिष्ट निष्पादन का अनुरोध किया था। मोइत्रा ने अंतरिम राहत के तौर पर हेनरी को हर महीने 10 दिनों के लिए उनके पास रहने देने की अनुमति मांगी थी। जिला अदालत ने 10 नवंबर को कहा कि मोइत्रा के पास हेनरी को हर महीने 10 दिन रहने की अनुमति देने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है और अदालत ने उनके पक्ष में अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय मोइत्रा की अपील पर अब अप्रैल में सुनवाई करेगा।

उत्तरी सेना के कमांडर ने लद्दाख के सियाचिन सेक्टर में युद्ध तैयारियों की समीक्षा की

लेह/जम्मू : भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने बृहस्पतिवार को सियाचिन सेक्टर का दौरा किया और सैनिकों की युद्ध क्षमता और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। सैन्य कमांडर ने दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे सैन्य क्षेत्रों में से एक में तैनात सैनिकों के पेशेवर रुख, साहस और समर्पण की सराहना की और विभिन्न पदों पर तैनात जवानों से आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने का आग्रह किया। उत्तरी कमान मुख्यालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा,''उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने युद्ध क्षमता और परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए

सियाचिन ब्रिगेड का दौरा किया।'' शर्मा ने सियाचिन स्की नोड का भी दौरा किया, जहां उन्होंने प्रशिक्षण ढांचे और स्कीइंग क्षमताओं का आकलन किया और बेहद कठिन जलवायु तथा भूभाग में कार्यरत सैनिकों के साथ बातचीत की। सैन्य कमांडर ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अपने दौरे के दौरान बुधवार को पूर्वी लद्दाख में अग्रिम चौकियों का भी दौरा किया, जहां उन्होंने सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की।

जनगणना 2027 में असमिया समुदाय लगभग अल्पसंख्यक हो जाएगा : हिमंत

गुवाहाटी : मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि 2027 की जनगणना में असमिया समुदाय 'लगभग' अल्पसंख्यक बन जाएगा। शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कहा कि वह 'बहुत ही कठिन समय' में राजनीति में हैं। उन्होंने इस बारे में अधिक ब्यौरा दिये कहा, ''2027 की जनगणना के दौरान, असमिया समुदाय लगभग अल्पसंख्यक बन जाएगा।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली असम सरकार उस 'दीपक' को जीवित रखने की कोशिश कर रही है, जो ''सभी को

साहस'' प्रदान करता है। उन्होंने कहा, ''आज धुबरी और माजुली दोनों जगहों से लोग मुझे फोन करके कहते हैं, 'मैं सुरक्षित हूं।' हम अल्पसंख्यक बनने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन केवल एक दीपक ही प्रकाश और साहस प्रदान कर रहा है।'' शर्मा ने इससे पहले भी कई मौकों पर दावा किया है कि अगर मौजूदा जनसांख्यिकी बदलाव जारी रही तो 2041 तक असम में मुसलमानों की आबादी लगभग हिंदुओं की आबादी के बराबर हो जाएगी। जनगणना-2011 के अनुसार, असम में कुल मुस्लिम आबादी 1.07 करोड़ थी जो राज्य के 3.12 करोड़ निवासियों का 34.22 प्रतिशत थी। इसके मुताबिक असम में 1.92 करोड़ हिंदू थे। भाजपा राज्य में जनसांख्यिकीय बदलाव को नियमित रूप से रेखांकित करती रही है। उसने दावा किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम नौ जिले मुस्लिम बहुल हो गए, जबकि 2001 में यह संख्या छह थी, और वर्तमान में यह संख्या बढ़कर कम से कम 11 हो गई है। हालांकि, 2021 में कोई जनगणना नहीं हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक 2001 की जनगणना के दौरान असम में 23 जिले थे जिनमें से छह जिले धुबरी (74.29 प्रतिशत), ग्वालपाड़ा (53.71 प्रतिशत), बारपेटा (59.37 प्रतिशत), नागांव (51 प्रतिशत), करीमगंज (52.3 प्रतिशत) और हैलाकांडी (57.63 प्रतिशत) मुस्लिम बहुल थे। आंकड़ों के मुताबिक 2011 की जनगणना के दौरान राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 27 हो गई और उनमें से नौ जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक थे।

असम के लोगों का राज्य के संसाधनों पर अधिकार है, न कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का: नवीन

गुवाहाटी : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि असम के संसाधनों पर अधिकार केवल असम की जनता का है, न कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का। नवीन ने डिब्रूगढ़ जिले के मनोहरी चाय बागान में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए घुसपैठियों के खिलाफ उचित कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, ''घुसपैठियों को वापस भेजने संबंधी मुख्यमंत्री की कार्रवाई से पता चलता है कि वह राज्य के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।'' भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्वोत्तर को प्राथमिकता देते हैं और इस क्षेत्र में ''प्रत्येक परियोजना की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं''। उन्होंने दावा किया, ''पिछली केंद्र सरकारों ने भी इस क्षेत्र के लिए धनराशि आवंटित की थी, लेकिन उसका उचित इस्तेमाल नहीं हुआ।'' उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के इस दौर में भी, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई नीतियों के कारण भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है।

न्यूज ब्रीफ

भारत की अंडर-17 पुरुष टीम म्यांमार के खिलाफ दो मैत्री मैच खेलेगी

नयी दिल्ली: भारत की अंडर-17 पुरुष फुटबॉल टीम तीन और पांच मार्च को यांगून में म्यांमार के खिलाफ दो मैत्री मुकाबले खेलेगी। भारतीय टीम एएफसी अंडर-17 एशियाई कप की तैयारी कर रही है जो सऊदी अरब में आयोजित होगा। टीम इस वर्ष अब तक चार अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच खेल चुकी है जिसमें दो ताजिकिस्तान (गोवा में) और दो तुर्किये (अंताल्या में) के खिलाफ रहे। तुर्किये से लौटने के बाद कोच बिबियानो फर्नांडिज की टीम गोवा में प्रशिक्षण जारी रखे हुए है। टीम 28 फरवरी को म्यांमार की राजधानी के लिए रवाना होगी। भारत की तरह म्यांमार ने भी एएफसी अंडर-17 एशियाई कप के लिए क्वालीफाई किया है। भारत ग्रुप डी में छह मई को ऑस्ट्रेलिया, 10 मई को उज्बेकिस्तान और 13 मई को दक्षिण कोरिया का सामना करेगा।

आईपीएल से जुड़ी 'द हंड्रेड' टीमों के पाक खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाने की संभावना

लंदन: पाकिस्तान के क्रिकेटरों को आगामी सत्र में 'द हंड्रेड' की उन फ्रेंचाइजी से अनुबंध मिलने में मुश्किल हो सकती है जिनका स्वामित्व आंशिक रूप से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीमों के पास है। रिपोर्टों के अनुसार इन टीमों ने अगले महीने होने वाली खिलाड़ी नीलामी में पाक खिलाड़ियों पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया है। 21 जुलाई से 16 अगस्त तक निर्धारित इस टूर्नामेंट के आगामी सत्र में निजी निवेश के कारण खिलाड़ियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी होने वाली है लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इस वित्तीय लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है क्योंकि भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंधों के चलते आईपीएल से जुड़ी फ्रेंचाइजी ऐसा फैसला कर सकती हैं।

अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हराकर जीत से अभियान समाप्त किया

चेन्नई: आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप डी के औपचारिक मुकाबले में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का समापन जीत के साथ किया। टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी दोनों टीमों के बीच खेले गए इस मैच में अफगानिस्तान हर विभाग में बेहतर साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने चार विकेट पर 200 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इब्राहिम जदरान ने 56 गेंदों पर नाबाद 95 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने सात चौके और पांच छक्के जड़ते हुए रन गति को लगातार बनाए रखा। जदरान को 54 रन पर जीवनदान मिला, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। सेदिकुल्लाह अटल ने 44 रन और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 30 रन का योगदान दिया। जदरान और अटल ने तीसरे विकेट के लिए 95 रन की अहम साझेदारी की। अंत में अजमतुल्लाह उमरजई ने सात गेंदों पर 13 रन बनाकर टीम को 200 के पार पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कनाडा की शुरुआत खराब रही और उसने तीसरे ओवर में कप्तान दिलप्रीत बाजवा का विकेट गंवा दिया। छह ओवर में स्कोर तीन विकेट पर 33 रन हो गया। मोहम्मद नबी ने घातक गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ सात रन देकर चार विकेट चटकाए। कप्तान राशिद खान ने भी दो विकेट लिए। हर्ष ठाकर (30) और साद बिन जफर (28) ने संघर्ष किया, लेकिन टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 118 रन ही बना सकी। कनाडा को टूर्नामेंट में एक भी जीत नसीब नहीं हुई।

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने दूसरे मैच में भारत को हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की

कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत को 19 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। अब निर्णायक मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला जाएगा।पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पांच विकेट पर 163 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया वोल (88) और बेथ मूनी (46) ने पहले विकेट के लिए 128 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की, जो भारत के खिलाफ महिला टी20 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ओपनिंग भागीदारी है। वोल ने 57 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के की मदद से 88 रन बनाए, जबकि मूनी ने 39 गेंदों पर 46 रन जोड़े। अरुंधति रेड्डी ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट करते हुए चार ओवर में 30 रन देकर दो विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत महिला क्रिकेट टीम ने तेज शुरुआत की। शेफाली वर्मा (29) और स्मृति मंधाना (31) ने पावरप्ले में 54 रन जोड़े। नौवें ओवर में टीम का स्कोर एक विकेट पर 65 रन था, लेकिन इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। कप्तान हरमनप्रीत कौर (36) और ऋचा घोष (19) ने चौथे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की, मगर बढ़ते रन रेट के दबाव में टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 144 रन ही बना सकी।ऑस्ट्रेलिया के लिए एश्ले गार्डनर ने 22 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि किम गार्थ, अनाबेल सदरलैंड और कप्तान सोफी मोलिनू ने दो-दो विकेट चटकाए।

पाक हॉकी विवाद : कप्तान बट पर प्रतिबंध के बाद पीएचएफ प्रमुख का इस्तीफा

कराची: पाकिस्तान हॉकी में चल रहा संकट बृहस्पतिवार को गहरा गया जब आस्ट्रेलिया दौरे की व्यवस्था में कुप्रबंधन के कारण खिलाड़ियों के सड़क पर रहने को लेकर पीएचएफ की आलोचना करने वाले कप्तान अम्माद शकील पर दो साल का प्रतिबंध लगाने के बाद महासंघ के अध्यक्ष तारिक बुगती ने पद से इस्तीफा दे दिया। बुगती ने कहा कि उन्होंने पीएचएफ के मुख्य संरक्षक प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने कहा ,'' मैने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है लेकिन उनसे और फील्ड मार्शल असीम मुनीर से आस्ट्रेलिया में प्रो लीग के दौरान हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह भी किया है।' उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आखिरी कार्रवाई के तौर पर राष्ट्रीय टीम के कप्तान अम्माद शकील बट पर दो साल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हॉकी खेलने पर प्रतिबंध लगाया जिनकी बयानबाजी से पाकिस्तान हॉकी की छवि खराब हुई। स्वदेश वापिस लौटने पर बट ने लाहौर में एक प्रेस कांफ्रेंस में पीएचएफ की आलोचना करके दौरे पर कुप्रबंधन के लिये उसे दोषी ठहराया।

गावस्कर की अभिषेक को सलाह, पारी के शुरू में 'एक्रॉस द लाइन' शॉट खेलने से बचें

अहमदाबाद: दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर का मानना है कि अभिषेक शर्मा मौजूदा टी20 विश्व कप में उम्मीदों के दबाव से जूझ रहे हैं और वह चाहते हैं कि यह आक्रामक सलामी बल्लेबाज अपनी पारी की शुरुआत में 'एक्रॉस द लाइन' शॉट खेलने से बचे। अभिषेक ने टूर्नामेंट में अभी तक जो तीन मैच खेले हैं उनमें वह खाता खोलने में नाकाम रहे हैं। अमेरिका, पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ वह शुरू में ही आउट हो गए थे। गावस्कर ने स्टार स्पोर्टस से कहा,'अभिषेक शर्मा बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन पर उम्मीदों का बोझ साफ दिख रहा है। अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ अच्छी शुरुआत की होती तो बात कुछ और होती। अब बड़े छक्के लगाने वाला शीर्ष बल्लेबाज होने का दबाव उन पर साफ दिख रहा है।' उन्होंने कहा, 'अपनी बल्लेबाजी क्षमता को देखते हुए उन्हें क्रीज पर समय बिताना होगा। उन्हें अपनी पारी की पहली ही गेंद पर चौका या छक्का लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर बड़े शॉट खेलने का मन करे तो ठीक है। लेकिन उन्हें 'एक्रॉस द लाइन' शॉट खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।' गावस्कर ने कहा कि इस 25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज को अपनी पारी की शुरुआत में समझदारी से क्रिकेट खेलने की जरूरत है।

गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 60 करोड़ रुपये का योगदान करेगा इंडियन ऑयल

लखनऊ: इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड गोरखपुर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपये का योगदान देगी। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार और कंपनी के बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक समझौते ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह स्टेडियम महज एक सुविधा नहीं होगा बल्कि पूर्वोत्तर प्रदेश की उभरती प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का एक मंच भी बनेगा। प्रस्तावित स्टेडियम की अनुमानित लागत 392.94 करोड़ रुपये है और इसमें 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। इसका निर्माण अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा। स्टेडियम में आधुनिक पिच, अभ्यास सुविधाएं, फ्लडलाइट, अत्याधुनिक ड्रेसिंग रूम, मीडिया सेंटर और उन्नत खेल अवसंरचना होगी जिससे यहां बड़े अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित किए जा सकेंगे। इस परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को छह विकेट से हराया

कोलंबो: जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप ग्रुप बी के आखिरी मैच में बृहस्पतिवार को श्रीलंका को छह विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाथुम निसांका के 62 रन की मदद से श्रीलंका ने सात विकेट पर 178 रन बनाये। जवाब में ब्रायन बेनेट (63) और कप्तान सिकंदर रजा (45) की पारियों के दम पर जिम्बाब्वे ने 19 . 3 ओवर में चार विकेट पर 182 रन बनाकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया।

वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से हराया

कोलकाता: वेस्टइंडीज ने गुरुवार को यहां टी20 विश्व कप के ग्रुप सी के मैच में इटली को 42 रन से हराकर लीग चरण के अपने चारों मैच में जीत हासिल करके सुपर आठ में जगह बनाई। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अनुकूल दिख रही पिच पर इटली के स्पिनरों के सामने खुलकर नहीं खेल पाए और उसकी टीम कप्तान शाई होप (46 गेंद पर 75 रन) के अर्धशतक के बावजूद छह विकेट पर 165 रन ही बना पाई। इसके जवाब में इटली की टीम 18 ओवर में 123 रन बनाकर आउट हो गई। वेस्टइंडीज की तरफ से शमर जोसेफ ने 30 रन देकर चार विकेट लिए।

एपस्टीन फाइल में नाम आने के विवाद के बीच एआई समिट से नदारद रहे गेट्स

नयी दिल्ली: माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में अपना पूर्व निर्धारित मुख्य भाषण नहीं दिया। उनके फाउंडेशन ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। हालांकि, फाउंडेशन ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन यह निर्णय तब आया है जब यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित दस्तावेजों में गेट्स का नाम आने के बाद आयोजकों ने उन्हें मंच देने पर असहजता व्यक्त की थी। सरकारी सूत्रों ने 17 फरवरी को ही कहा था कि एपस्टीन प्रकरण के खुलासे से बहुत पहले गेट्स को दिया गया निमंत्रण वापस ले लिया गया है और वह 16 फरवरी से शुरू हुए इस पांच दिवसीय सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। उस दिन गेट्स फाउंडेशन के एक प्रवक्ता ने इस बात का खंडन करते हुए कहा था कि वह वास्तव में भाग ले रहे हैं।

एआई में तेजी से प्रगति करने वाला युग लाने की क्षमता है: गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई

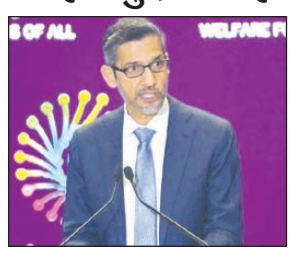

नयी दिल्ली: गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई ने बृहस्पतिवार को कृत्रिम मेधा (एआई) को 'तीव्र प्रगति'' के युग की शुरुआत करने वाली प्रौद्योगिकी करार दिया जिसमें नई वैज्ञानिक खोजों को संभव बनाने एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं को विकास के पारंपरिक चरणों को पार करने में मदद करने की क्षमता है। उन्होंने साथ ही कहा कि कृत्रिम मेधा जितना किसी भी प्रौद्योगिकी ने उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित नहीं किया। 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' को संबोधित करते हुए गूगल एवं अल्फाबेट के सीईओ ने एआई के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की, इसे ' हमारे जीवनकाल का सबसे बड़ा बदलाव'' बताया और सरकारों, कंपनियों एवं संस्थानों से इस प्रौद्योगिकी को साहसपूर्वक एवं जिम्मेदारी से आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'यह हमारे जीवनकाल का सबसे बड़ा वैश्विक बदलाव है। हम तीव्र प्रगति और नई खोजों के मुहाने पर हैं जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पुरानी कमियों को दूर करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि यह परिणाम न तो निश्चित है और न ही स्वचालित। ऐसी एआई बनाने के लिए जो वास्तव में सभी के लिए उपयोगी हो, हमें साहसपूर्वक प्रयास करना होगा, जिम्मेदारी से काम लेना होगा और इस निर्णायक क्षण में मिलकर काम करना होगा।'

एआई सम्मेलन में अंबानी, अदाणी के समूहों ने 210 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता जताई

एआई को मोबाइल, इंटरनेट की तरह सस्ता बनाएंगे: अंबानी

नयी दिल्ली: अरबपति मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी की अगुवाई वाले उद्योग समूहों ने भारत को कृत्रिम मेधा (एआई) विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अवसंरचना निर्माण में कुल 210 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अंबानी ने यहां आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान अगले सात वर्षों में गुजरात के जामनगर में गीगावाट-स्तर के एआई-सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये (करीब 110 अरब अमेरिकी डॉलर) के निवेश की घोषणा की। यह परियोजना 10 गीगावाट तक के हरित ऊर्जा अधिशेष का उपयोग करेगी और दूरसंचार एवं डिजिटल सेवा प्रदाता जियो के नेटवर्क के साथ एकीकृत 'एज-कम्प्यूट' परत के माध्यम से देशभर में बहुत कम देरी वाली एआई सेवाएं उपलब्ध कराएगी। अंबानी ने कहा, 'हमारा संकल्प स्पष्ट है, जिस तरह आज कनेक्टिविटी हर जगह उपलब्ध है, उसी तरह एआई को भी सर्वसुलभ बनाना है। जब कंप्यूटिंग क्षमता एक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित हो जाएगी, तो नवाचार अपने-आप तेजी से बढ़ेगा। दूसरी तरफ, अदाणी की अगुवाई वाले अदाणी समूह ने वर्ष 2035 तक नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बहुत बड़े स्तर के एआई-सक्षम डेटा सेंटर विकसित करने के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना पेश की। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा एवं कंप्यूटिंग प्रतिबद्धता है। इस पहल से सर्वर विनिर्माण, क्लाउड मंच और सहायक उद्योगों में अतिरिक्त 150 अरब डॉलर के निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इससे भारत में लगभग 250 अरब डॉलर की एआई अवसंरचना पारिस्थितिकी विकसित हो सकती है। अदाणी समूह के कार्यकारी निदेशक जीत अदाणी ने कहा कि भारत को आयात पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का एआई ढांचा विकसित करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि एआई आने वाले समय में राष्ट्रीय संप्रभुता को नए सिरे से परिभाषित करेगा।

भारत में इसी साल शुरू हो जाएगा दुर्लभ स्थायी चुंबक का उत्पादनः किशन रेड्डी

नयी दिल्ली: कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत में इसी साल से दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (आरईपीएम) का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक वाहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम होगा। दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, पवन चक्कियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैमानिकी और रक्षा क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। रेड्डी ने यहां उद्योग मंडल फिक्की और खान मंत्रालय की तरफ से आयोजित सम्मेलन में कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत सरकार दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, इस क्रम में इसी साल भारत में स्थायी चुंबकों का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब भारत नियोडिमियम और प्रासियोडिमियम जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। खान मंत्रालय ने इसके लिए अन्वेषण ब्लॉकों की नीलामी करने के साथ पुनर्चक्रण सुविधाओं को भी मंजूरी दी है। फिलहाल भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त इकाइयों की कमी है और यह एक बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के लिए सरकार आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात में महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र पार्क स्थापित करने की तैयारी में है।

एआई कंपनियों, भारतीय नवोन्मेषकों का संकल्प समावेशी एवं जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देना: वैष्णव

नयी दिल्ली: कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़ी अग्रणी कंपनियों और भारत के नवोन्मेषकों ने 'नयी दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स' के तहत रोजगार सहित विभिन्न नीतिगत मुद्दों के समर्थन में वास्तविक दुनिया में एआई के उपयोग की समझ बढ़ाने तथा बहुभाषी और संदर्भ-आधारित मूल्यांकन को मजबूत करने का संकल्प किया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के निष्कर्षों की घोषणा करते बृहस्पतिवार को हुए कहा कि 'नयी दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स' के तहत अग्रणी एआई कंपनियां और भारत के नवोन्मेषक जैसे सर्वम, भारतजन, यानी और सोकेट...एक साझा दृष्टिकोण के साथ स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के समूह पर सहमत हुए हैं जो समावेशी एवं जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा, यह पहल एआई के काम करने के तरीके पर 'ग्लोबल साउथ' नीत दृष्टिकोण के निर्माण में भारत को अग्रणी बनाएगी जो नवाचार को समानता एवं वास्तविक प्रभाव के साथ संतुलित करती है।' मंत्री ने बताया कि इस संकल्प के तहत कंपनियों ने दो महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं की हैं। पहली, वास्तविक दुनिया में एआई के उपयोग की समझ को बढ़ाना। इसके लिए गुमनाम एवं समेकित आंकड़ों के आधार पर रोजगार, कौशल व आर्थिक बदलाव जैसे विषयों पर साक्ष्य-आधारित नीतिनिर्माण का समर्थन किया जाएगा। वहीं दूसरी प्रतिबद्धता है, एआई प्रणालियों के बहुभाषी व संदर्भ-आधारित मूल्यांकन को मजबूत करना, ताकि एआई विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों एवं वास्तविक उपयोग परिदृश्यों में प्रभावी ढंग से काम कर सके, खासकर 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील) देशों में।

अनिल अंबानी का शीर्ष अदालत में हलफनामा, 'बिना इजाजत देश नहीं छोड़ूंगा'

नयी दिल्ली: रिलायंस (एडीएजी) के चेयरमैन अनिल अंबानी ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा देकर कहा है कि वह बिना पूर्व-अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे और एजेंसियों के साथ जांच में पूरा सहयोग करेंगे। यह मामला अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) द्वारा कथित रूप से 40,000 करोड़ रुपये की बैंकिंग एवं कॉरपोरेट धोखाधड़ी से जुड़ा है। शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में अंबानी ने कहा कि उनका देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और न ही उनकी कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोई मंशा है। अंबानी ने कहा, 'मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने जुलाई, 2025 से मौजूदा जांच शुरू होने के बाद से भारत नहीं छोड़ा है और फिलहाल देश से बाहर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है।' उन्होंने साथ ही वादा किया कि यदि उन्हें किसी काम से विदेश जाना पड़ा तो वह उससे पहले अदालत की अनुमति लेंगे।'

न्यूज अपडेट

चांदी 18,000 रुपये की छलांग के साथ 2.6 लाख रुपये पर, सोना 1,950 रुपये मजबूत

नयी दिल्ली: देश की राजधानी में बृहस्पतिवार को बहुमूल्य कीमती धातुओं की कीमतों में सात प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। चांदी जहां 2.6 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, वहीं सोना 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गया। यह उछाल वैश्विक रुख तथा अमेरिका एवं ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की मांग में बढ़ोतरी की वजह से आया। स्थानीय बाजार के जानकारों के मुताबिक, चांदी बुधवार के 2,46,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बंद स्तर से 18,000 रुपये या 7.32 प्रतिशत बढ़कर 2,64,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर मिलाकर) हो गई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 1,950 रुपये या 1.24 प्रतिशत बढ़कर 1,58,650 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर मिलाकर) हो गया। पिछले सत्र में यह 1,56,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

एयरबस की कर्नाटक संयंत्र से सालाना 10 हेलिकॉप्टर के विनिर्माण की योजना

नयी दिल्ली: भारतीय बाजार की वृद्धि संभावनाओं को लेकर उत्साहित दिग्गज वैमानिकी कंपनी एयरबस की कर्नाटक में टाटा एडवांस्ड सिस्टम के सहयोग से स्थापित अपनी 'फाइनल असेंबली लाइन' (एफएएल) से साल 2029 तक सालाना 10 एच-125 हेलीकॉप्टर के उत्पादन की योजना है। एयरबस हेलिकॉप्टर्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ब्रूनो ईवन ने हेलिकॉप्टर को 'राष्ट्र निर्माण' और सार्वजनिक सेवाओं के एक सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि भारत में इसके लिए एक समूची पारिस्थितिकी के विकास के प्रयास जारी रहेंगे। ईवन ने यहां 'पीटीआई-भाषा' के साथ खास बातचीत में कहा, 'हम भारत में हेलिकॉप्टर बाजार की संभावनाओं पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। हमारा मानना है कि एच-125 हेलिकॉप्टर भारत में असैन्य हेलिकॉप्टर बाजार को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।'

टाटा समूह एआई चिप के विकास की दिशा में सक्रियः चंद्रशेखरन

नयी दिल्ली: टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने बृहस्पतिवार को कहा कि समूह कृत्रिम मेधा (एआई) के समूचे प्रौद्योगिकी ढांचे के विकास पर काम कर रहा है और उद्योग-विशिष्ट एआई चिप विकसित करने की दिशा में भी पहल शुरू कर दी गई है। चंद्रशेखरन ने यहां आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के दौरान पीटीआई-भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विभिन्न क्षेत्रों पर एआई के व्यापक प्रभाव को देखते हुए टाटा समूह औद्योगिक समाधानों से लेकर डेटा सेंटर और क्षेत्र-विशिष्ट एआई समाधानों तक कई स्तरों पर अपनी क्षमता विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा, हम समय के साथ उद्योग के हिसाब से अलग-अलग एआई-आधारित चिप विकसित करना चाहते हैं। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है, हालांकि इसकी समय-सीमा बताना अभी संभव नहीं है। समूह द्वारा विकसित किए जा रहे शुरुआती सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल वाहन क्षेत्र में किए जाने की संभावना है।

भारत, न्यूज़ीलैंड ने बागवानी में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की

नयी दिल्ली: भारत और न्यूज़ीलैंड ने बृहस्पतिवार को बागवानी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें भारतीय बाज़ार में 'कीवी' रूटस्टॉक फल का आयात भी शामिल है। एक सरकारी बयान के अनुसार, भारत और न्यूज़ीलैंड ने बागवानी सहयोग पर साझा कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक बुलाई। यह 12 मार्च, 2025 को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए सहमति सहयोग (एमओसी) के तहत एक अहम कदम है। भारत और न्यूज़ीलैंड की जेडब्ल्यूजी बैठक की सह-अध्यक्षता कृषि विभाग के संयुक्त सचिव (बागवानी) प्रिय रंजन और न्यूज़ीलैंड की तरफ से द्विपक्षीय संबंध एवं व्यापार विभाग के 'डिविजनल मैनेजर', स्टीव एन्सवर्थ ने की। बयान में कहा गया कि बैठक में दोनों तरफ के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ, बागवानी क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आए, जिसमें कीवी फल और पिप फल (सेब और नाशपाती) के विकास पर खास ध्यान दिया गया। रंजन ने बताया कि कीवीफल को भारत के लिए एक प्राथमिक फसल के तौर पर पहचाना गया है।

वर्ष 10, पूर्णांक 3509 अंक 319 RNI No WBHIN/2016/66788, सर्वांग प्रकाशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सरोज राय द्वारा रजि. 17, बालमुकुन्द मक्कर रोड, 2सरा तल्ला, कोलकाता-700 007 से प्रकाशित। एल. एस. पब्लिकेशन्स प्रा. लि. 4, कैनल वेस्ट रोड, कोलकाता-700 015 से मुद्रित।
सम्पादक- अनिल कुमार राय (पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी), कॉर्पोरेट आफिस : 230, चित्तरंजन एवेन्यू, कोलकाता-700 006, विज्ञापन एवं प्रसार-9874555256/7044444522, ई-मेल news@samagya.in